twitter.com/divyadelhi | facebook.com/divyadelhi | infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | गुरूवार, 14 अगस्त, 2025 | वर्षः 12, अंकः 268, पृष्ठः 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में बचाव पक्ष के तीन गवाहों के बयान दर्ज

नई दिल्ली

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले के आरोपित सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में आज बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों के बयान दर्ज हुए। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को करने का आदेश दिया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा एहतियात की वजह से सज्जन कुमार को जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। आज सुनवाई के दौरान तीन गवाहों श्री भगवान, डॉ. विजय वत्स और बाला कृषण क्षेत्री ने बयान दर्ज किए गए। बता दें कि ने 07 जुलाई को सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था। सज्जन कुमार ने कहा था कि वो इस अपराध में सपने में भी शामिल हो सकता और मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। 9 नवंबर 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे। अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था। 23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153अ, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

सीबीआई को यूपीपीएससी अधिकारियों की जांच की अनुमति मिली

लखनऊ

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2010 में अपर निजी सचिव भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार मामले में अधिकारियों की जांच की अनुमति मिल गईं है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस भर्ती मामले में चार सितंबर 2018 को सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की थी। सीबीआई ने 30 सितंबर 2020 को नियुक्त विभाग से तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, तीन अधिकारियों के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-17ए के तहत जांच करने की अनुमति मांगी थी।

बिहार एसआईआर वोटर के खिलाफ नहींः सुप्रीम कोर्ट

एसआईआर कवायद मतदाताओं को सुविधा देने का एक कदमः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निर्वाचन आयोग का दस्तावेज जांच अभियान 'मतदाता विरोधी' नहीं

नई दिल्ली

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निर्वाचन आयोग का दस्तावेज जांच अभियान 'मतदाता विरोधी' नहीं है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह कवायद लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश है। यह सुनवाई बुधवार यानी 13 अगस्त 2025 को जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच के सामने हुई, जिसमें कोर्ट ने मतदाता-अनुकूल रुख को रेखांकित किया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में याचिका पर बहस करते हुए दस्तावेज जांच को एंटी वोटर और अलगावादी बता दिया, लेकिन जस्टिस बागची ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा, "हम आपका आधार से जोड़कर अलगाव का तर्क समझते हैं। मगर बात दस्तावेजों की संख्या की है, जो असल में मतदाताओं के हक में है, उनके खिलाफ नहीं। जरा देखें, कितने सारे दस्तावेजों से आप नागरिकता साबित कर सकते हैं।"

'अगर 11 दस्तावेज मांगते हैं तो...'

जस्टिस बागची की बातों का समर्थन करते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, "अगर 11 दस्तावेजों की मांग की जाए, तो यह मतदाता विरोधी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक दस्तावेज मांगा जाए, तो..." कोर्ट ने साफ किया कि निर्वाचन आयोग का यह कदम मतदाताओं को सुविधा देने वाला है, न कि उन्हें परेशान करने वाला है।

एसआईआर की वजह से 65 लाख से ज्यादा मतदाता प्रभावितः विपक्ष

नई दिल्ली

बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का मुद्दा देशभर में छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। वहीं, सुनवाई के दौरान सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक महिला और एक पुरुष को कोर्ट में पेश करते हुए दावा किया कि उन्हें बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 'मृत' घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की वजह से 65 लाख से ज्यादा मतदाता प्रभावित हुए हैं।

चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान असफल रहा है। योगेंद्र यादव की दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है। आयोग ने कहा कि अगर ऐसी गलती हुई है, तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसे सुधार सकते थे।

वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने में मदद करें पार्टियांः चुनाव आयोग

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना। चुनाव आयोग के वकील ने योगेंद्र यादव के कदम का विरोध जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की हरकतों के बजाय आप लोगों की मदद करें। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि हमने राजनीतिक दलों से अपने एजेंट नियुक्त करने को कहा था। यह कहकर कि लोकतंत्र खतरे में है, रोने के बजाय वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने में हमारी मदद करें। हाल ही में सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाली 34 वर्षीय मिंता देवी के वोटर आईडी कार्ड में उनकी उम्र 124 वर्ष छप गई। वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग के स्टैंड का समर्थन भी किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है।

चुनाव आयोग की बात पर जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमें कम से कम इस बात पर गर्व है कि हमारे नागरिक इस कोर्ट में अपनी बात रखने आ रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या हटाने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया है।

'आधार नागरिकता को पक्का सबूत नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आधार कार्ड को निवास का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को निवास का अंतिम और पक्का सबूत नहीं माना जा सकता है। खासकर, बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान। सीनियर वकील कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोझ झा की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि लोग आधार, राशन और मतदाता पहचान पत्र रखते हैं। लेकिन, अधिकारी इसे किसी भी चीज का पक्का सबूत नहीं मान रहे हैं।

'आधार निर्णायक सबूत नहीं'

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये दस्तावेज यह दिखा सकते हैं कि आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इन्हें निर्णायक सबूत नहीं कहा जा सकता है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कई विसंगतियां हैं, जैसे जिन लोगों को मृत बताया गया वे जिंदा हैं और जिनकों जिंदा बताया गया वे मृत भी पाए गए हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि यह विवाद चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच भरोसे की कमी के कारण बढ़ा है।

जस्टिस कांत ने यह भी कहा कि यह कहना बहुत व्यापक होगा कि बिहार में किसी के पास वैध दस्तावेज ही नहीं है।

चुनाव आयोग के वकील का तर्क

चुनाव आयोग के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के बड़े पैमाने के काम में कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी होने से पहले सुधारा जा सकता है।

बता दें, विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों ने 24 जून को चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर वोटरों को बाहर किया गया, तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा।

क्या है विपक्ष की चिंता?

बता दें, 1 अगस्त को मसौदामतदाता सूची जारी की गई है, जबकि अंतिम सूची 30 सितंबर को आएगी।

इस पर विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों वैध मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। याचिकाएं फ्खऊ टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे), जेएमएम, के साथऔर योगेंद्र यादव ने मिलकर दायर की है।

आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा विचार करेंगेः चीफ जस्टिस

नई दिल्ली

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने आश्वासन दिया। उखक ने एक सीनियर एडवोकेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) की याचिका का भी कोर्ट में जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग) रूल, 2001, का पालन नहीं किया जा रहा है। 2001 का यह नियम आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को कम करने के लिए नियमित नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों को जरूरी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्तेः 70% को सालभर में टीके लगेंगे, एडवायजरी जारी

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर सड़क से हटाने और उन्हें विशेष शेल्टर होम में भेजने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के बाद छिड़ी बहस के बीच नई जानकारी समाने आई है। केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं द्वारा आमजन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है।

तीनों मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। इनमें 70% का वैक्सीनेशन व नसबंदी एक साल में करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा 2019 की पशु गणना के अनुसार देश में 50 लाख बेसहारा पशु हैं। इस अभियान में पहली बार ग्राम पंचायतें भी जुड़ेंगी। अभियान के लिए राज्यों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मदद लेने को कहा गया है।

रूस के सस्ते तेल का आम आदमी को फायदा नहीं

तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी, सरकार भी 46% टैक्स वसूल रही

मुंबई

बीते 3 साल से भारत को 5 से 30 डॉलर प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है। इस डिस्काउंट का 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को मिला। वहीं सरकार को 35% फायदा मिला। आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आया। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। उन्होंने इसका कारण रूस से तेल खरीद को बताया है। ट्रम्प का कहना है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां इसे प्रोसेस करके यूरोप और अन्य देशों में बेच देती हैं। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। जवाबः भले ही तेल की कीमतें कागज पर डी-रेगुलेटेड हों, लेकिन रिटेल कीमतें सरकार और तेल कंपनियों के नियंत्रण में हैं। सरकार को टैक्स से स्थिर आय चाहिए और तेल कंपनियां पुराने LPG सब्सिडी के नुकसान का हवाला देकर अपने मार्जिन को जायज ठहराती हैं।

नतीजा यह है कि सस्ते तेल का फायदा कंपनियों और सरकार के खजाने में जा रहा है, न कि आम लोगों की जेब में। पेट्रोल और डीजल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। इसके अलावा, राज्य सरकारें वैल्यू-एडेड टैक्स लगाती हैं।

अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर कारोबारी घराना, अडाणी परिवार दूसरे स्थान परः रिपोर्ट

नई दिल्ली

देश के अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाला अंबानी परिवार 28 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ सबसे समृद्ध कारोबारी घराना है, जबकि अडाणी परिवार 14.01 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। शोध एवं रैंकिंग फर्म हुरुन ने जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। हुरुन की ओर से बार्कलेज के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार के पास 28 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। यह अडाणी परिवार की 14.01 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति से दोगुनी से भी अधिक है। हुरुन ने कारोबारी घरानों की संपत्ति में पिछले एक साल में आए बदलाव पर यह रिपोर्ट बार्कलेज के साथ मिलकर तैयार की है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि देश के 300 सबसे मूल्यवान भारतीय परिवारों के पास 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (140 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा की संपत्ति है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 40 फीसदी से भी अधिक है। वहीं, अकेले अंबानी परिवार की संपत्ति देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 12 फीसदी है। हुरुन-बार्कलेज की रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार की संपत्ति में पिछले वर्ष 10 फीसदी की वृद्धि हुई।

ई केवाईसी से वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रही गैस सब्सिडी

जयपुर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई केवाईसी) का प्रावधान मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के लिए किया गया है।

उल्लेखनीय है कि योजना का लाभ असल हकदारों तक पहुंचाने के लिए आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) लाभार्थियों की सटीक पहचान, वास्तविक समय और लागत की प्रभावी गणना, प्रमाणीकरण और डी. डुप्लीकेशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधार प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीकों में से बायोमेट्रिक (चेहरा, उंगली, आँख की पुतली आधारित) प्रमाणीकरण सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय साबित हुआ है। यह योजना के दुरुपयोग को रोकने और सब्सिडी लाभ को इच्छित प्राप्तकताओं तक पहुंचाने को सुनिश्चित करता है।

बर्ड फ्लू के दृष्टिगत प्राणी उद्यानों में निगरानी एवं सतर्कता बरती जाएः योगी

● एच5 एवियन इंफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के संभावित खतरे को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

लखनऊ

एच5 एवियन इंफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संबंधित विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राणी उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनेटाइज किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर ब्लो टॉचिंग की प्रक्रिया भी अपनाई जाए। सभी वन्य जीवों और पक्षियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से हो और उनके आहार की गहन जांच के बाद ही भोजन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर को देखते हुए तय की जाए, ताकि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन हो सके। सभी कर्मचारियों को एवियन इंफ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और उससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जाए। साथ ही उन्हें पीपीई किट सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे सुरक्षित रहकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। पोल्ट्री सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप कड़ी निगरानी की जाए। पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर निरंतर नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को यह भी निर्देश दिया कि H5 एवियन इंफ्लुएंजा के मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि संक्रमण की कोई श्रृंखला मानव समाज तक न पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) सहित अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए।

भारत तकनीक, नए विचारों और 'मेक इन इंडिया' पहलों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है : बलवंत सिंह राजपूत

गांधीनगर। गुजरात सरकार के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने कहा, 'भारत तकनीक, नए विचारों और 'मेक इन इंडिया' पहलों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। एमएसएमईएस के लिए यहां अपार संभावनाएं और अवसर मौजूद हैं।'

उद्योग मंत्री राजपूत गांधीनगर के एक होटल में भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग, गुजरात सरकार के उद्योग एवं खनन विभाग, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लघु उद्योग भारती के सहयोग से संयुक्त रूप से 'रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता' विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और देश 'आत्मनिर्भर भारत' व 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में निजी कंपनियों के साथ-साथ अब एमसएमईएस(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की भूमिका भी बहुत अहम हो गई है। उन्होंने कहा कि गुजरात के पास इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस टेक्सटाइल और विशेष सामग्रियों का मजबूत औद्योगिक आधार है, जिससे वह देश के रक्षा निर्माण में बड़ा योगदान दे सकता है। लेकिन कई गुजरात-आधारित एमसएमईएस को अभी भी राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने में कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य इन चुनौतियों को दूर करना और एमसएमईएस को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग की संयुक्त सचिव मनीषा चंद्रा ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तथा गुजरात की संभावनाओं पर विशेष संबोधन दिया। भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने भी इस विषय पर अपने विचार साझा किए। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष बलदेवभाई प्रजापति ने भी अपना विशेष संबोधन दिया।

गुजरात सरकार के उद्योग एवं खनन विभाग की प्रधान सचिव ममता वर्मा ने अपने मुख्य भाषण में कहा, वर्तमान में इस क्षेत्र में 16,000 एमसएमईएस कार्यरत हैं। गुजरात में इस क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि वे सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएँ और सक्रिय नीतियों का सदुपयोग करें जिससे देश में रक्षा क्षेत्र की क्षमता और अधिक विकसित होगी। इसके अलावा मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ए.के. चन्नन ने रक्षा खरीद प्रक्रिया पर अपने विचार साझा किए। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सौमेंदु रे ने रक्षा स्टार्टअप्स और नवाचार पर प्रस्तुति दी। सिडबी के उप महाप्रबंधक एस. मुरलीधरन, एलएंडटी प्रिसिजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स के सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर आनंद मिस्त्री तथा एचएएल के डिप्टी जनरल मैनेजर जावेद अली ने अपने संबोधनों में 'रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता' को भारत के लिए समय की आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की टीम ने अपने 100 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन और एयरोस्पेस, रक्षा, हथियार आदि के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ। इस अवसर पर रक्षा निर्माण क्षेत्र की कई कंपनियों जैसे एचएएल-हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, अभ्युदय भारत प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., यूनिक फोर्ज राजकोट, इनसाइड एफपीवी ड्रोन, कृष्णा इंजीनियरिंग, एसएलएस सिस्टम लेवल सॉल्यूशन, उर्जा प्रोडक्ट्स प्रा. लि., वेक्समा टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., एक्सियो इंस्पायर्ड मेड टेक, सिडबी, स्पाइक इंजीनियरिंग आदि के स्टॉल भी प्रदर्शित किए गए।

तमिलनाडु के कोयंबटूर में मनाया जाएगा विश्व हाथी दिवस

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तमिलनाडु वन विभाग के साथ मिलकर कोयंबटूर में विश्व हाथी दिवस समारोह का आयोजन करेगा। यह वार्षिक आयोजन, हाथियों के संरक्षण और उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उपायों को मज़बूत करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि कोयंबटूर में होने वाले इस कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और वन्यजीव विशेषज्ञ भाग लेंगे जो विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री कीतिवर्धन सिंह और तमिलनाडु सरकार के वन एवं खादी मंत्री आरएस राजाकन्नप्पन भी उपस्थित रहेंगे। विश्व हाथी दिवस समारोह के अंतर्गत कोयंबटूर में मानव-हाथी संघर्ष पर एक केंद्रित कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य हाथी-क्षेत्र वाले राज्यों को मानव-हाथी सह-अस्तित्व से संबंधित अपनी चुनौतियों को साझा करने और अपने-अपने क्षेत्रों में लागू किए जा रहे संघर्ष के समाधान उपायों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह पहल प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत चल रहे प्रयासों के अनुरूप है, जो मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है।

'हर घर तिरंगा' एक अभियान नहीं, भावनात्मक आंदोलन हैः शेखावत

एजेंसी

नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में शुरू किए गए 'हर घर तिरंगा' अभियान के चौथे संस्करण की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य देशभर के नागरिकों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपने घरों और दिलों में उतारने के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस वर्ष हम तिरंगा अभियान का चौथा संस्करण मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कराया है। ये युवा लोगों को तिरंगा अभियान के लिए प्रेरित करेंगे। नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा, हर घर तिरंगा एक अभियान से कहीं बढ़कर है, यह एक भावनात्मक आंदोलन है, जो 1.4 अरब भारतीयों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के शाश्वत रंगों के तले एकजुट करता है। इसका उद्देश्य देशभक्ति को जगाना, नागरिक गौरव को बढ़ावा देना और हमारे लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के जीवंत प्रतीक के रूप में तिरंगे के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों और राष्ट्रीय ध्वज के बीच के रिश्ते को औपचारिक और संस्थागत संबंध से गहरे व्यक्तिगत बंधन में बदलने के लिए संकल्पित, हर घर तिरंगा प्रत्येक भारतीय को भारत की स्वतंत्रता के उत्सव को चिह्नित करते हुए गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है।उन्होंने कहा को इस पहल का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है- तिरंगा घर लाना न केवल व्यक्तिगत जुड़ाव की अभिव्यक्ति है बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि है। यह हमारी आज़ादी के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है और एकता, अखंडता और प्रगति के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिज्ञा भी है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तिरंगा अभियान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। गृह मंत्रालय के अपर सचिव अभिजीत सिन्हा और जल शक्ति मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार समीर कुमार ने अपने-अपने मंत्रालयों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि संस्कृति मंत्रालय इस अभियान का नोडल मंत्रालय है और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों और आम जनता के साथ मिलकर काम कर रहा है।

देश में हर घर तिरंगा देशभक्ति फिल्म महोत्सव का शुभारंभ

एजेंसी

नई दिल्ली। हर घर तिरंगा- देशभक्ति फिल्म महोत्सव का तीन दिवसीय आयोजन आज से पूरे देश में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) की है। दिल्ली में इस आयोजन का शुभारंभ शहीद और स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर आधारित फिल्मों के साथ हुआ, जिसे दर्शकों से अत्यधिक सराहना मिली। दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई और पुणे में आयोजित इस प्रोग्राम में केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों, कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों ने भाग लिया। दिल्ली में कपिल मिश्रा ने, मुंबई में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और अभिनेत्री श्रेया पिलगांवकर कार्यक्रम में शामिल हुईं। इसके अलावा चेन्नई में फिल्म निर्माता वसंत, कोरियोग्राफर कला मास्टर और अभिनेत्री नमिता जैसी हस्तियां शामिल रहीं। पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने पूरे समारोह का सीधा प्रसारण प्रस्तुत किया।दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सिनेमा में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को अमर बनाने और पीढ़ियों को प्रेरित करने की शक्ति है। हर घर तिरंगा, देशभक्ति फिल्म महोत्सव केवल सिनेमा का उत्सव नहीं है, बल्कि उस यात्रा की याद दिलाता है जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई।

भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है : शहनवाज हुसैन

भागलपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर के परिसदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। क्योंकि उन्हें भाजपा का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भाजपा के खिलाफ नकारात्मक राजनीति करती है और देशहित के कार्यों पर भी राजनीति से बाज नहीं आती है। उन्होंने हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस अभियान में हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी, लेकिन कांग्रेस को इसमें खुशी नहीं हुई। देश के दुश्मनों पर करारा वार करने के बाद भी कांग्रेस का चेहरा मुरझाया क्यों था? यह जनता से छुपा नहीं है। उन्होंने इसे कांग्रेस की देशहित-विरोधी सोच बताया और दावा किया कि इस रवैये का जवाब जनता चुनाव में देगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार में अभूतपूर्व विकास हुआ है। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हमेशा इस विकास कार्य पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की है, जबकि कांग्रेस केवल सत्ता में बने रहने और राजनीतिक लाभ के लिए काम करती है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शाहनवाज हुसैन ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है।

पार्टी के खिलाफ बयान देने वाले कर्नाटक के सहकारिता मंत्री का इस्तीफा

बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने अपने विवादास्पद बयान के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देश पर अपने बेटे राजेंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। दरअसल, 8 अगस्त को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया था। इस बयान के जवाब में राजन्ना ने कहा था, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने बिना मतदाता सूची की जांच किए अब यह बात कही है। मतदाता सूची तब तैयार हुई थी, जब हमारी अपनी सरकार सत्ता में थी, तब हमने आंखें क्यों मूंद लीं? जैसे ही इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया था। यह वीडियो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आलाकमान को भेजा। वेणुगोपाल ने जांच के बाद इसे राहुल गांधी के संज्ञान में लाया था।

धराली आपदा के 98 पीड़ित परिवारों को बांटे पांच-पांच लाख के चेक

- पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्य को प्राथमिकता से किया जाएगा पूरा
- प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है राज्य सरकारः मुख्यमंत्री

एजेंसी

देहरादून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली आपदा के 98 प्रभावित परिवारों को धामी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में पांच-पांच लाख रुपये के चेक सौंप दिए गए है। सरकार ने आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। पिछले सप्ताह 5 अग्रस्त को उत्तरकाशी एवं पौड़ी जनपदों में प्राकृतिक आपदा ने व्यापक तबाही मचाई थी। कई स्थानों पर भारी बारिश, भूस्खलन और मलबे के प्रवाह से घर पूरी तरह नष्ट हो गए और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ। इससे प्रभावित परिवारों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। आपदा पीड़ितों केलिए आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने धराली में 98 परिवारों को राहत राशि के चेक वितरित किए। इस मौके पर आपदा प्रभावितों ने सहायता राशि त्वरित मिलने पर धामी सरकार का धन्यवाद दिया।इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं क्षेत्रीय नागरिक भी उपस्थित रहे।

सात दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी समिति

इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने एक बयान जारी कर कहा कि आपदा पीड़ित क्षेत्र में रहने वाले लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनकी मदद के लिए हमारी सरकारउनके साथ खड़ी है। पीड़ितों को सहायता राहत वितरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा भवनों, आवासों, होमस्टे, पशुधन और बागानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो सात दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक व्यापक राहत एवं पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा, जिससे प्रभावितों को दीर्घकालिक सहयोग मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्य को प्राथमिकता के साथ अंजाम दिया जाएगा, ताकि सभी प्रभावित जल्द से जल्द सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।

धराली आपदा का आठवां दिनः हर्षिल में भागीरथी में बनी झील से पानी की निकासी के साथ ही लापता लोगों की तलाश में शुरू अभियान में तेजी

एजेंसी

देहरादून। उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद हर्षिल में गंगा भागीरथी नदी में बनी झील से पानी की निकासी के साथ ही लापता लोगों की खोज को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने आपदा में अपने घर खो चुके लोगों को 5-5 लाख की तत्काल सहायता के चेक भी वितरित किए हैं। गंगोत्री र के विधायक सुरेश चौहान ने बताया कि प्रभावितों को सहायता राशि दे दी गई है और अब लापता की तलाश को लेकर अभियान तेज किया जा रहा है।

धराली आपदा का आज आठवां दिन है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू का कार्य पूरा होने के बाद अब लापता लोगों की तलाश पर सरकार फोकस है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने भी आपदा की समीक्षा की और उन्होंने अब झील से पानी की निकासी के साथ ही लापता की खोज तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल मंडल के आयुक्त के अनुसार, 43 लोग लापता हैं और उन्हें जल्द खोजने जाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

हर्षिल में बनी झील से पानी की निकासी को लेकर प्रयास तेज किए गए। झील से मलबा हटाते वक्त एक जेसीबी भी झील में समा गई। चालक, परिचालक ने जेसीबी से कूद कर जान बचाई।

झील से पानी की निकासी के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम, सिंचाई विभाग के साथ अन्य विभाग भी लगातार जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि निचले इलाकों को सर्तक किया गया है और जल्द ही झील से पानी की निकासी सुरक्षित तरीके से कर ली जाएगी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी में वैली ब्रिज से वाहनों की आवाजाही होने के बाद अब डबरानी में मार्ग पर आवाजाही शुरू करने का कार्य भी आज तेज हुआ है।

बीएसएफ ने हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा

एजेंसी

कठुआ/हीरानगर। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने कठुआ जिले के राजबाग हीरानगर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सतर्क बीएसएफ जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठिए को चुनौती दी। जब उसने बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया, तो बीएसएफ ने गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। बाद में उसे पकड़ लिया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद सुरक्षा घेरे में उसे एक स्थानीय चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। इस संबंध में मामले की जांच की जा रही है और एजेंसियां उसकी पहचान और सीमा पार करने के उसके मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान के समक्ष विरोध दर्ज कराया जा रहा है।

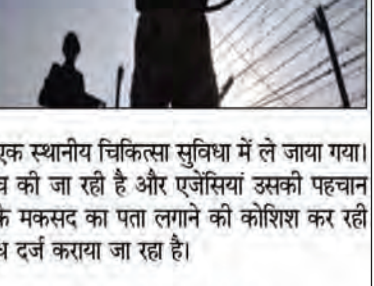

सीईए की पहली परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न, सहकारी चुनावों में पारदर्शिता पर जोर

एजेंसी

नई दिल्ली। सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) ने यहां राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरणों के साथ अपनी पहली परामर्शदात्री बैठक की। बैठक का उद्देश्य राज्यों के सहकारी चुनाव अधिकारियों के साथ एक संवाद तंत्र विकसित करना था ताकि देशभर में सहकारी निकायों के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें। बैठक की अध्यक्षता सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने की। इसमें ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के चुनाव आयुक्तों सहित सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद कुमार झा, सीईए के उपाध्यक्ष आरके गुप्ता और सहकारिता लोकपाल आलोक अग्रवाल ने भाग लिया। सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने सहकारी क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। मार्च 2024 से अब तक सीईए द्वारा 159 चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं और आने वाले समय में 69 अन्य चुनावों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। बैठक में उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता, चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा, निर्वाचन अधिकारियों के लिए पुस्तिका, राष्ट्रीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के चुनाव तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। देवेंद्र कुमार सिंह ने सहकारी चुनावों में अमिट स्याही के प्रयोग, चुनाव चिन्ह निर्धारण तथा सदस्यों की शेयर पूंजी जैसे विषयों पर भी विचार रखे और राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए। सीईए ने निर्णय लिया कि हर तीन महीने में एक परामर्शदात्री बैठक आयोजित की जाएगी ताकि सहकारी चुनाव सुधारों की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके। बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख राज्य प्रतिनिधियों में ओडिशा से श्रीकांत पुस्ती, बिहार से गिरीश शंकर व कुमार शांत रक्षित, तमिलनाडु से तिरु दयानंद कटारिया, महाराष्ट्र से अनिल महादेव कवाडे व अशोक गाडे, तथा तेलंगाना से जी श्रीनिवास राव शामिल रहे।

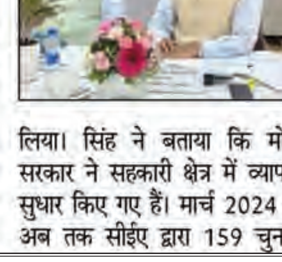

श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर जन्माष्टमी के दिन 'ऑपरेशन सिंदूर' के महिमा मंडन की तैयारी

एजेंसी

नई दिल्ली। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण के 5252वें प्राक्ट्योत्सव पर भारत की सशस्त्र सेनाओं के विश्वभर में सराहे गए पराक्रम का महिमा मंडन होगा। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर युगल सरकार भगवान श्रीकृष्ण और राधाजी, पूर्णावतार भगवान श्री केशवदेव जी महाराज सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। 16 अगस्त को मनाए जाने वाली जन्माष्टमी की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने एक विशेष बातचीत में कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। कपिल शर्मा ने बताया कि युद्धकौशल, कूटनीति और पराक्रम के प्रतीक 'ऑपरेशन सिंदूर' ने हर भारतीय के अन्दर गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार किया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भारतीय सेना के पराक्रम का महिमा मंडन होगा। कपिल शर्मा ने कहा, दैवीय शक्ति, नारीशक्ति और मंगल के प्रतीक सिंदूर ने प्रत्येक देशवासी को गौरवान्वित किया है। आज पूरा विश्व भारत के राष्ट्रवादी कुशल नेतृत्व, अतुलनीय सैन्य क्षमता और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपूर्व संकल्प शक्ति को देखकर अचंभित है। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण के प्राक्ट्योत्सव पर आने वाले लाखों लाख भक्त सिंदूर पुष्प बंगले में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंतलीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करके अविभूत होंगे। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भक्त सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करेंगे वो भी आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करेंगे। महोत्सव के सभी आयोजन शास्त्रीय परंपराओं के अनुरुप होंगे।

मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 188 मोबाइल फोन बरामद

एजेंसी
नई दिल्ली । दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ यूनिट ने डीटीसी बसों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान गौतमपुरी निवासी राजेश के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 188 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपये है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस भी बरामद किया है। आरोपित के खिलाफ पहले भी चोरी, डकैती, शस्त्र अधिनियम के 13 मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। दक्षिण पूर्वी जिले के डीसीपी डा. हेमंत तिवारी ने बताया कि सात अगस्त को स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि डीटीसी बसों में यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का सरगना राजेश गौतमपुरी में आटो रिक्शा पर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापामारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी के 188 मोबाइल फोन बरामद किए।पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि उसके साथी डीटीसी बसों में सफर करने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते और उनका मोबाइल फोन चोरी कर लेते हैं। वारदात के दौरान वह आटो लेकर बस के साथ-साथ चलता था। फोन चोरी करने के बाद उसके साथी चोरी का फोन उसे देकर दूसरी बस में चढ़ जाते थे। पुलिस उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए उससे पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस ने उसके आटो को भी जब्त कर लिया है।

आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान में लगे हैं : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता सालों से आवारा कुत्तों की समस्या से परेशान है। इस मसले पर पिछली सरकारों ने जो किया और दिल्ली नगर निगम में जो चल रहा था, वह सबको पता है। सीएम ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार इस मसले पर चर्चा के साथ-साथ समाधान के प्रयासों में लगी है। उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये समस्या विकराल रूप धारण कर खड़ी है। हम पूरी योजना बनाते हुए इस पर काम करेंगे ताकि दिल्ली की जनता को राहत मिले।भाजपा नेता विजय गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने हमारी 'नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट' की मांग का समर्थन किया। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगले आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। इस कदम से रोजाना सामने आने वाले लगभग दो हजार कुत्तों के काटने के मामलों में कमी आएगी और खासतौर पर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जो सबसे अधिक शिकार हो रहे हैं, उन्हें राहत मिलेगी।

कर्ज चुकाने से बचने के लिए दफ्तर में चलवाई गोली, तीन पकड़े गए

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले के मौजपुर में एक बिल्डर ने कर्ज चुकाने से बचने के लिए अपने ही दफ्तर पर फायरिंग की साजिश रची। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर एक नाबालिग समेत तीन लोगों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक नौ अगस्त की दोपहर जाफराबाद थाना पुलिस को सूचना मिली कि विजय मोहल्ला, मौजपुर की गली नंबर 8, सना पब्लिक स्कूल के पास फायरिंग हुई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीश मिले। उन्होंने बताया कि वह बिल्डर हैं। दोपहर 2:30 बजे जब वह अपने दफ्तर पहुंचे, तो खिड़की का शीशा टूटा हुआ मिला। उन्हें शक था कि यह फायरिंग उस व्यक्ति ने कराई है, जिससे उन्होंने पैसे उधार लिए थे। मौके से पुलिस को एक खाली कारतूस बरामद हुआ। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस अधिकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने मुरसलीन को दबोचा। पूछताछ में मुरसलीन ने खुलासा किया कि वह अनीश के लिए काम करता है और अनीश के कहने पर ही उसने एक नाबालिग से पिस्तौल से फायरिंग करवाई। पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस मुरसलीन से बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने अनीश और 16 वर्षीय नाबालिग को पकड़ा।

हत्या के मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 13 साल से हत्या के मामले फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित को वर्ष 2012 में चाची की हत्या के मामले में अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था। पकड़े गए आरोपित की पहचान वेलकम निवासी सोनू उर्फ अजय (43) के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार 29 जनवरी 2012 को वेलकम थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते आरोपित अशोक, भरत, हीरा, सोनू और बबलू ने भरत की दूसरी पत्नी राजरानी उर्फ राजकुमारी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में गंभीर रूप से झुलसने के बाद पीड़िता की मौत हो गई। मामले में 08 फरवरी 2012 को मुकदमा दर्ज किया गया था। 09 जुलाई 2012 को आरोपित सोनू, अशोक कुमार, हीरा देवी और बबलू को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया। बाद में अशोक कुमार और हीरा को पकड़ लिया गया, लेकिन सोनू और बबलू फरार रहे। डीसीपी के अनुसार इंस्पेक्टर मंजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार निगरानी और तकनीकी ट्रैकिंग कर रही थी।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत, यूक्रेन में शांति बहाली का समर्थन

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी।प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की का आभार व्यक्त करते हुए यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए भारत की दृढ़ और सतत स्थिति को दोहराया। उन्होंने इस दिशा में भारत की ओर से हरसंभव समर्थन प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई।पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से उन्हें अवगत कराया। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने और

यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत की। हमने हमारी द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मैं प्रधानमंत्री का हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभारी हूं। उन्होंने आगे कहा, मैंने हमारे शहरों और गांवों पर, खासकर कल जोपोरिजिया में बस स्टेशन पर हुए रूसी हमलों के बारे में बताया, जहां एक सामान्य शहरी सुविधा पर रूस के जानबूझकर किए गए बमबारी में दर्जनों लोग घायल हुए। यह तब हो रहा है, जब युद्ध को समाप्त करने की कूटनीतिक संभावना अंततः दिखाई दे रही है, लेकिन रूस युद्धविराम के लिए तत्परता दिखाने के बजाय केवल कब्जे और हत्याओं को जारी रखने की अपनी इच्छा दिखा रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस रुख को साझा करता है कि यूक्रेन से संबंधित हर निर्णय में यूक्रेन की भागीदारी होनी चाहिए। अन्य तरीकों से परिणाम नहीं मिलेंगे।दोनों नेताओं के बीच रूस पर प्रतिबंधों को लेकर भी बात हुई। जेलेंस्की ने कहा, हमने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर भी विस्तार से चर्चा की। मैंने कहा है कि रूसी ऊर्जा, विशेष रूप से तेल के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है।

चाकू घोंपकर युवक की हत्या, तीन गिरफ्तार

एजेंसी
नई दिल्ली । मध्य दिल्ली के नबी करीम इलाके में पुरानी रंजिश में एक युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बंसी उर्फ पाली (22) के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम टीम के अलावा एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया। बाद में बंसी का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा गया। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपित परवेश उर्फ ऋषि (20), पंकज उर्फ काके (22) और अजय (28) को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि पांच से छह बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का दावा है कि एक स्कूटी खरीद-फरोख्त को लेकर हुए विवाद में बंसी की हत्या हुई। वहीं सूत्रों का कहना है कि एक युवती से शादी करने को लेकर चल रही तनातनी के बीच वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर बाकी आरोपितों की तलाश कर रही है। मध्य जिले के डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि बंसी अपने परिवार के साथ अमरपुरी, नबी करीम इलाके में रहता था। इसके परिवार में पत्नी के अलावा दस माह का बेटा व बड़ा भाई सोनू है। बंसी कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में कपड़े बेचने का काम करता था। रविवार रात करीब 11.30 बजे पुलिस को एक युवक की हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। छानबीन के दौरान पता चला कि आरोपित बंसी के बड़े भाई सोनू को ढूंढते हुए एरिया में पहुंचे थे। इन लोगों ने सोनू पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। भाई पर हुए हमले को देखकर बंसी उसे बचाने आया तो आरोपितों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया।

विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समन का दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया जवाब

एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 9 शामनाथ मार्ग बंगले पर अत्यधिक खर्च पर आवाज उठाने के लिए दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के जारी समन का जवाब दिया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि दिल्ली विधानसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के नियम 82 को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में 'मैं न तो विधानसभा का सदस्य हूं और न ही सदन सत्र में है।' देवेंद्र यादव ने अपने जवाब में बताया कि यह कल्पना से परे है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित की जा रही एक कमेटी उस मामले की जांच कैसे कर सकती है, जिसमें अध्यक्ष स्वयं शिकायतकर्ता हैं। देवेंद्र ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और विभिन्न न्यायिक निर्णयों के खिलाफ है। देवेंद्र यादव ने अपने जवाब में कहा कि एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस गरीबों, दलितों,

किसानों, महिलाओं और युवाओं से संबंधित जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी। कांग्रेस के लीगल एवं मानवाधिकार विभाग के चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार के साथ वकीलों का एक समूह देवेंद्र यादव का जवाब उन्हें सौंपने और समन की अवैधता के बारे में बताने के लिए विशेषाधिकार कमेटी के अध्यक्ष से मिलना चाहता था, लेकिन उनके वकीलों से मिलने से इनकार किया गया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का जवाब विशेषाधिकार कमेटी के अध्यक्ष कार्यालय में जमा करा दिया गया।

मुख्यमंत्री ने विस के मानसून सत्र का रिपोर्ट कार्ड किया पेश, बोलीं- तीन अहम विधेयक पारित कर रचा इतिहास

एजेंसी
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि 04 से 08 अगस्त तक चले इस सत्र में पांच महीने के कार्यकाल में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित करके उनकी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने पिछली सरकार की विफलता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आआपा) की सरकार पांच साल में महज 14 विधेयक ही पास कर पाई। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सीएजी रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष के भ्रष्टाचार को उजागर किया बल्कि फांसीघर जैसे भ्रामक ऐतिहासिक फेरबदल पर भी आआपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता राजनीतिक नौटंकी नहीं बल्कि रचनात्मक बहस और जनसमस्याओं के समाधान पर केंद्रित शासन है। हर विधायक को बोलने का अवसर मिला, विपक्ष को भी बराबर का समय दिया गया ताकि सदन वास्तव में जनता की आवाज बन सकें। उन्होंने दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि मात्र पांच महीना में 3 अहम विधेयक पारित जबकि पिछली सरकार ने पूरे पांच वर्षों में केवल 14 विधेयक पारित किए थे। उनमें से अधिकांश वेतन संशोधन और जीएसटी से संबंधित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियम 280 के तहत सदस्यों ने अपने मुद्दे सदन में रखे और 62 विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि वर्षों से लंबित दिल्ली स्कूल शिक्षा (पारदर्शिता एवं शुल्क विनियमन) विधेयक पारित बहुमत से पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्र में पेश दो सीएजी रिपोर्ट ने पूर्ववर्ती आआपा की सरकार के शासन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं की पोल खोल दी। यमुना सफाई, अमृत योजना और अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मिले फंड का सही उपयोग नहीं किया गया। यहां तक 52,000 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र तक दाखिल नहीं किए गए। कई योजनाएं सिर्फ कागजों में चलती रहीं, जबकि जनता को कोई लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा परिसर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा फैलाए गए झूठ और प्रोपेगेंडा को को खारिज किया। 'फांसी घर' जैसी नकारात्मक राजनीति जो न सिर्फ ऐतिहासिक फेरबदल की कोशिश थी बल्कि सदन के गौरवपूर्ण इतिहास पर कालिख पोतने का कार्य भी था। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ फांसी घर के भ्रम को खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया सदन कानून निर्माण और जनहित के लिए है, न कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की और बताया कि स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत सरकार की तरफ से 22 लाख तिरंगे वितरित किए जाएंगे।

'इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025' में 652 टीमों ने किया रजिस्ट्रेशन : सिरसा

एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली की उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार के प्रमुख इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025 को स्टूडेंट इनोवेटर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इसमें 652 टीमों ने चार कैटेगरी में मुकाबला करने और अपने समाधान उद्योग जगत व सरकारी तंत्र के सामने पेश करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें इनाम की कुल राशि 40 लाख रुपये है। एक बयान में बताया गया है कि यह प्रतियोगिता दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीएआईआईडीसी) द्वारा उद्योग विभाग, जीएनसीटीडी की ओर से आयोजित की जा रही है। इसका आधिकारिक नॉलेज पार्टनर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। इसमें छात्रों को दिल्ली की औद्योगिक चुनौतियों के लिए तकनीक-आधारित, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को तैयार करने का अवसर मिलेगा। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हिस्सा ले रहे छात्रों की ऊर्जा और उत्साह की सराहना करते

हुए कहा कि दिल्ली के युवा हमारे औद्योगिक भविष्य को आकार देने का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह साबित करता है कि वे उन मुद्दों को हल करने के लिए तैयार हैं जिनका हमारे उद्योग रोज सामना करते हैं। 652 रजिस्ट्रेशनों में से 124 शॉर्टलिस्टेड टीमें अब 13 अगस्त को नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में होने वाले प्रीलीमिनरी राउंड में भाग लेंगी। इस आठ घंटे की चुनौती में वे चार प्रमुख केस स्टडीज पर काम करेंगी। दिल्ली के औद्योगिक हब्स में लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स की अक्षमताएं और बिखरी हुई सप्लाई चेन (175 एंट्रीज), स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए टेक सॉल्यूशंस (188 एंट्रीज), दिल्ली की छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को अपनाना (125 एंट्रीज) और वित्त, बाजार और तकनीक तक पहुंच के माध्यम से एमएसएमईएस को मजबूत बनाना (164 एंट्रीज) है।

प्रीलीमिनरी राउंड के बाद 40 फाइनलिस्ट टीमें- प्रत्येक कैटेगरी से शीर्ष दस 22 अगस्त के ग्रैंड फिनाले में पहुंचेंगी, जहां वे अपने समाधान उद्योग और सरकारी तंत्र के सामने पेश करेंगी। सिरसा ने कहा कि इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन के जरिए हम शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच एक समन्वय बना रहे हैं। छात्रों को वास्तविक समस्याओं पर काम करने का मौका मिल रहा है, जबकि नीति निर्माताओं को देश के उज्ज्वल दिमागों से निकले आइडियाज से सीधे रूबरू हो रहे हैं।

युवक की चाकू घोंपकर हत्या, मुकदमा दर्ज

एजेंसी
नई दिल्ली। । उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सुबह एक युवक की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रजी अहमद(33) के रूप में हुई। आज सुबह उसका खून से लथपथ शव एक खाली प्लॉट में मिला। गला रेतने के अलावा उसके पेट, कमर, गर्दन और हाथ पर चाकू के साथ निशान थे। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को शव के पास से ही शराब की खाली बोतल के अलावा चार गिलास बरामद हुए। जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की पहचान करने में जुटी है। आशंका है कि आरोपितों ने शराब पिलाने के बाद रजी अहमद को मौत के घाट उतारा। एक से अधिक व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से छानबीन कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि रविवार रात रजी को उसका ही एक दोस्त घर से बुलाकर ले गया था। उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि रजी अपने परिवार के साथ गली नंबर-1, हरकेश मार्केट, खजूरी खास में किराए के मकान में रहता था। इसके परिवार में दो पत्नियां और चार बच्चे हैं। रजी पीओपी का काम करता था। इसके माता-पिता और परिवार के बाकी सदस्य बिहार में रहते हैं। रजी की पत्नी तबस्सुम खातून ने बताया कि उसके पति घर पर मौजूद थे।

पौधे लगाना सिर्फ कार्यक्रम नहीं, भविष्य का निवेश है: महापौर

एजेंसी
नई दिल्ली। । दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने बीएसएफ कैंप छावला में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में हिस्सा लिया और एक पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण, हवा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि आज का दिन दिल्ली के हरित इतिहास में दर्ज होने वाला है। सिर्फ एक घंटे में इस परिसर में एक हजार पौधे और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में एक लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भव्य वृक्षारोपण अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान 'एक पेड़ मां के नाम' को साकार करता है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए पेड़ लगाना है, जो सैनिकों की तरह देश की सेवा करते हैं। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करके पर्यावरण की रक्षा करते हैं, जैसे सैनिक सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हैं। इकबाल सिंह ने कहा कि लोग प्रकृति और हरियाली देखने के लिए पहाड़ों और जंगलों में जाते हैं, लेकिन दिल्ली में ही पर्याप्त पेड़ हों, तो

यहीं प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा और अच्छी ऑक्सीजन के लिए पेड़ों की जरूरत है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। महापौर ने कहा कि यह वृक्षारोपण ड्राइव एक जागरूकता अभियान है। जो हर नागरिक को प्रेरित करती है कि वह अपने हिस्से का एक पौधा अवश्य लगाए।

राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम स्वच्छ दिल्ली के संकल्प के साथ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। यह एक स्वच्छ, सुंदर और हरित दिल्ली की दिशा में एक कदम है। इस कार्यक्रम में उपमहापौर जय भगवान यादव के साथ बीएसएफ आईजी संजय गौड़ और डीआईजी पीएस भट्टी भी मौजूद रहें।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि देश प्रेम और साहस की कोई उम्र नही होती। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मां भारती के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा कि बोस के बलिदान की अमिट गाथा सभी राष्ट्रभक्तों के लिए प्रेरणापुंज है।सचदेवा ने बताया कि महज 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीद खुदीराम बोस का आज 118वां शहादत दिवस है। उल्लेखनीय है कि खुदीराम बोस का आज 118वां शहादत दिवस है।

एक आदमी की नासमझी और एक परिवार की वजह से देश नुकसान नहीं झेल सकता : किरेन रिजिजू

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी सांसदों के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग तक मार्च पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बिना नाम लेते हुए कहा कि एक आदमी की नासमझी और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। किरेन रिजिजू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है। अब हम देश और संसद का समय और बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना चाहती है। आज हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे। एक आदमी की नासमझी और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। रिजिजू के मुताबिक, कई विपक्षी सांसदों ने भी आकर कहा कि वे असहाय हैं। उनके नेता उन्हें

जबरदस्ती हंगामा करने के लिए कहते हैं। यहां संसद में चुनकर आए हैं, जनता की बात रखने के लिए। हर दिन, हम देश और संसद का समय एक मुद्दे पर बर्बाद नहीं होने देंगे, इसलिए हम महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज भी उन्होंने (विपक्ष ने) चुनाव आयोग जाने के लिए समय मांगा और चुनाव आयोग ने इंडी गठबंधन को प्रत्येक पार्टी से दो सदस्यों को भेजने के लिए कहा। 30 सदस्यों को बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए। इंडी गठबंधन में, वे उन 30 लोगों को तय नहीं कर पाए। अब, खड़गे कह रहे हैं कि सभी विपक्षी सदस्य वीआईपी हैं, तो क्या 150 लोग चुनाव आयुक्त के कमरे में प्रवेश करेंगे? उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उन्हें संसद पर भरोसा नहीं है। वे हमारे देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करते हैं। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बार-बार नाटक क्यों करते हैं? जनता ने हमें देश सेवा के लिए भेजा है, न कि यहां नाटक करने के लिए भेजा है। हम विपक्ष से अपनी आखिरी अपील करते हैं। हम बिल पारित करेंगे। आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए। विपक्ष के लोग बाद में झूठ नहीं बोलें कि हमें बोलने नहीं दिया। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

चुनाव आयोग की तरफ से भाजपा बैटिंग कर रही है : इमरान मसूद

एजेंसी
नई दिल्ली । बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा गरमाया हुआ है। 'इंडिया' ब्लॉक के सांसदों ने सोमवार को इसके विरोध में संसद भवन से निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक मार्च निकालने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दी और हिरासत में ले लिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को तंज कसते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने से कहा, चुनाव आयोग पर उठाए हर सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। क्या भाजपा चुनाव आयोग की प्रवक्ता है? दोनों की सांठगांठ है। ऐसा नहीं है तो फ्रंटफुट में भाजपा क्यों खेलना चाह रही है? हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से है और हम उनसे सवाल कर रहे हैं।उन्होंने कहा, चुनाव आयोग से हमारे जो सवाल हैं, वह स्पष्ट हैं। चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज हमें दिए, उसमें झूठ

पकड़कर हमने उसे जनता के सामने रख दिया। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, लेकिन आयोग की तरफ से भाजपा बैटिंग कर रही है। ऐसे में दोनों का गठजोड़ साफ दिखाई दे रहा है।उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर कांग्रेस नेता ने सरकार पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह उनका एजेंडा है। अगर सामने कोई दूसरा होगा, तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर उनकी विचारधारा के लोग होंगे, तो वे समझा-बुझाकर मामले को शांत करेंगे। कुछ लोग धर्मस्थल के अंदर जाकर तोड़-फोड़ कर रहे हैं और पुलिस हाथ जोड़कर लोगों को निकाल रही है। ये क्या तमाशा है? वे ऐसी नफरतों को कहां पर लेकर जाएंगे? वे जो बो रहे हैं, उसे काटना भारी हो जाएगा। उन्होंने अमेरिका द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने पर कहा, पाकिस्तान खुद आतंकवादी है। ऐसे में अमेरिका सबसे बड़े आतंकवादी को संरक्षण दे रहा है। आईएमएफ से लोन दे रहा है। ऐसे में अमेरिका क्यों आतंकवाद की बात कर रहा है? गाजा में नरसंहार हो रहा है, लेकिन अमेरिका उस पर एक शब्द नहीं बोलता है।

संपादकीय

विज्ञान में लोक को प्रतिष्ठित करने की मुहिम

विज्ञान को आधुनिक युग में तेजी से धर्म का दर्जा दिया जा रहा है। लोगों में सबकुछ को वैज्ञानिक घोषित करने की ललक बढती जा रही है । ऐसा हो भी क्यों न ? विज्ञान विश्वसनीय, पूर्वाग्रहमुक्त और पक्षपातहीन अंतिम सत्य का पर्यायवाची जो हो गया है। हालाँकि सदैव ऐसा नहीं होता और स्वयं विज्ञान के अर्थ भी बदल रहे हैं। तब भी आँखिन देखी पर विश्वास करने वाली विज्ञान की विधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक भरोसेमंद आधार के रूप में सुबुद्ध लोगों की अभी भी पहली पसंद बनी हुई है। टोना-टोटका, झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र और ओझाझ्रसोखा को ले कर लोग हिचकने लगे हैं। आमतौर पर विज्ञान की बढ़ती साख का ही नतीजा है कि विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लगातार प्रयास हो रहे हैं ताकि आम जनों में वैज्ञानिक मानसिकता (साइंटिफिक टेम्पर) का विकास हो सके और वे खुशहाल जीवन बिता सकें। भारत में होशंगाबाद और केरल में समाज को विज्ञान से जोड़ने की पहल शुरू हुई थी जिसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार न हो सका। यहाँ एक जुड़ा सवाल वैज्ञानिक साक्षरता का भी है क्योंकि विज्ञान के प्रति भावनात्मक रुझान ही काफी नहीं हो सकती उसकी मुलभूत जानकारी भी आवश्यक है । चूँकि विज्ञान का क्षितिज निरंतर विस्तृत हो रहा है इसलिए वैज्ञानिक साक्षरता का स्तर भी बढ़ता रहता है और उसे नए ज्ञान के आलोक में बार-बार परिभाषित और पुर्नपरिभाषित किए जाने की जरूरत पड़ती है। गौरतलब है कि दुनिया और उसमें होने वाली घटनाओं को लेकर उत्सुकता सदा से वैज्ञानिकों के अध्ययन और विज्ञान के विकास के लिए एक बड़ा प्रेरक स्रोत रही है। परंतु विकसित हो रहे ज्ञान तक पहुँच सिर्फ बिरले और चुनिंदा लोगों की ही हो पाती है जो पहले से विशेष प्रकार का अध्ययन और औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके रहते हैं। यह बात एक हद तक तो समझ में आती है पर इस तरह विकसित होता ज्ञान-सृजन व्यापक लोक-जीवन से प्रायः अछूता ही बना रहता है। ज्ञान और समाज के बीच में एक बड़ी खाई या दूरी बनी रहती है जिससे ज्ञान पर कुछ लोगों या समूहों का एकाधिकार और वर्चस्व समाज में शोषण और असंतुलन पैदा करता है। मानवता का इतिहास इसका गवाह है कि ज्ञान में जिसे बढ़त रही वही विजयी रहा।

आज भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उन्नत रूप को लेकर विकसित राष्ट्रों के द्वारा इसी युक्ति से दबदबा बनाया जा रहा है। सत्य यही है कि समाज का बहुलांश या कहें एक बहुत बड़ा तबका ज्ञान-विज्ञान से अनभिज्ञ और ज्ञान-प्रक्रिया से बहिष्कृत-सा ही बना रहता है। इस तरह के अपरिचय के कारण उनको उस ज्ञान से लाभ मिलना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। शिक्षा के सामाजिक वितरण में असमानता का मुद्दा जन-कल्याण के व्यापक लक्ष्य को पाने में बड़ी बाधा बन जाता है और अनेक स्तरों पर बना हुआ है।

लोकतंत्र की दृष्टि से इस तरह का भेदभाव समाज को ज्ञानसम्पन्न होने के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा बन जाता है। ज्ञान के अभाव का परिणाम यह होता है कि न केवल सामाजिक-आर्थिक विषमताएं पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती चली आती हैं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध भी होता है और समाज शैक्षिकझ्रआर्थिक तौर पर पिछड़ जाता है। आज के तथाकथित ज्ञान युग में भी देश के अनेक समुदाय ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देश भी ज्ञान सृजन और ज्ञान के अनुप्रयोग की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस विसंगति के समाधान के लिए ज्ञान पर एकाधिकार से आगे बढ़ कर उसका व्यापक पैमाने पर प्रसार जरूरी है।

इधर कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय जगत में ज्ञान के प्रजातंत्री- करण को लेकर गंभीरता के कुछ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। इस सिलसिले में शुरू हुई ह्लजन-विज्ञानह्ल (सिटीजन साइंस) नाम की पहल उल्लेखनीय है। यह पहल गैर व्यवसायी वैज्ञानिकों या नागरिक जनों द्वारा वैज्ञानिक शोध में सक्रिय भागीदारी की परिघटना को व्यक्त करती है। इसे सक्रिय प्रतिभागी अनुसंधान (ऐक्शन रिसर्च) का ही एक रूप कहा जा सकता है। इसमें विभिन्न मात्रा में शोध कार्य करने के दौरान उसके विभिन्न चरणों में जन-भागीदारी को अवसर दिया जाता है। यह भागीदारी अप्रत्यक्ष और निष्क्रिय सहयोग से आरम्भ हो कर शोध में प्रत्यक्ष सहयोग-सहकार की सीमा तक जा सकती है। उल्लेखनीय है कि यूरोपियन कमीशन, अमेरिकी सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाओं और व्यवस्थाओं द्वारा जन-विज्ञान की पहल को अब विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

आज की दुनिया में औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जिस तेजी से हो रहे हैं उसे देखते हुए समाज विज्ञानों के लिए जन-विज्ञान की पहल का महत्व और बढ जाता है। आज के परिवेश में लोगों के व्यवहार, संज्ञान, निर्णय-प्रक्रिया, प्रेरणाएँ, भावनाएं, मनोवृत्तियाँ, सहयोग तथा संघर्ष आदि के नए-नए आयाम उभर रहे हैं जिनको समझने के लिए परम्परागत समाज विज्ञान अपर्याप्त है। उसके लिए एक व्यापक सामाजिक आधार वाली दृष्टि की जरूरत है। सामाजिक विज्ञानों में आम जन शोध में प्रतिभागी के रूप में भाग लेते हैं और शोधकर्ता उनसे विभिन्न प्रकार के आँकड़े प्राप्त करता है जिसके अंतर्गत प्रतिभागी शोधकर्ता के कहे अनुसार बोल कर, लिख कर या कोई कार्य करते हुए अथवा दैहिक मापक के जरिए आवश्यक आँकड़े उपलब्ध कराता है।

इस चरण के बाद शोधकर्ता और प्रतिभागियों के बीच सम्पर्क न अपेक्षित होता है न वांछित। वह नहीं के बराबर ही रहता है क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने प्रयोग और अन्य दूसरे अध्ययनों में वैज्ञानिक प्रक्रिया में जन-भागीदारी बाधक मानी जाती है इसलिए वह उसके प्रति उदासीन ही रहती है। वह उसे सशक्त भी नहीं करती क्योंकि शोधकर्ता और प्रतिभागी के बीच एक ज्ञान-शक्ति का अंतर है जिसे बनाए रखा जाता है। परंतु सत्य यह भी है कि प्रतिभागियों की निष्क्रिय भागीदारी अलगाव का भाव पैदा करने वाली साबित हो सकती है।

वोट के अधिकार के बाद सूचना का अधिकार है सबसे महत्वपूर्ण

सुभाष, हरियाणा के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता हैं। सूचना अधिकार कानून की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए 19 साल से प्रयासरत हैं। सूचना अधिकार कानून पर सरल भाषा में दो पुस्तिकायें प्रकाशित करवाई हैं ताकि सूचना अधिकार कानून की जानकारी आम जन तक पहुंच सके।

ये पेशे से स्वतंत्र पत्रकार हैं और कई अखबारों में स्वतंत्र रूप से लेखन भी कर चुके हैं। विभिन्न विषयों पर 200 से ज्यादा लेख विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में छप चुके हैं।

ह्यउत्पीड़न के शिकार बच्चोंह्ल की अनुभव के आधार पर ह्यसिसकता बचपनह्ल पुस्तिका भी लिखी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सूचना अधिकार कानून पर साधारण भाषा में सूचना अधिकार कानून कैसे करें-इस्तेमाल और सूचना का अधिकार-एक परिचय पुस्तिकाएं प्रकाशित की, जिसकी करीब 20 हजार प्रतियां लोगों तक पहुंचाई गई। सूचना के अधिकार कानून के बारे में जानकारी देते पर्चे और 10 हजार ब्रोशर भी प्रदेश भर में सूचना अधिकार कानून पर आयोजित सेमिनारों व गोष्ठियों में बंटवा चुके हैं। दैनिक जागरण के ह्यसांझीह्ल के लिए ही 25 के करीब लेख लिख चुके हैं। नवसाक्षरों के लिए 5 पुस्तकें भी लिख चुके हैं जिनमें ह्यरोशनीह्ल, ह्यहमारे नायक उदमीरामह्ल, ह्यप्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. रामधन सिंहह्लह्ल, ह्यह्यबाबु बाल मुकुन्दगुप्त और ह्यनई राहह्ल प्रमुख हैं।

गांव हो या शहर छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाओं, गोष्ठियों और सेमिनारों के माध्यम से लोगों को सूचना अधिकार कानून एवं इसके इस्तेमाल के बारे में बता रहे हैं। वे सूचना अधिकार कानून पर आयोजित सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में बताते हैं कि हमारा जानना क्यों जरूरी है?

जिन लोगों सूचना अधिकार कानून की जरूरत उन पर कानून की पहूंच नहीं

सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुभाष का कहना है कि सूचना अधिकार कानून पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। वास्तव में जिन लोगों को इस कानून की सबसे ज्यादा जरूरत है उन तक इसकी जानकारी पहूंची ही नहीं है। अभी तो बहुत ज्यादा प्रचार की जरूरत है? इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने प्रदेश भर के सूचना अधिकार से जुड़े कार्यकताओं को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2007 में हरियाणा सूचना अधिकार मंच का गठन किया। जिसमें प्रदेश भर के करीब सात हजार कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। मंच के गठन में आरटीआई कार्यकर्ता अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही। लेकिन बाद ये लोग सूचना अधिकार कानून के छोड़ कर राजनीतिक मंच पर आ गए। दूसरी और मंच के राज्य संयोजक के रूप में काम करते हुए उन्होंने मंच की जिला इकाइयों के माध्यम से सूचना अधिकार कानून की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई।

सुभाष का कहना है कि वोट के माध्यम से जहां हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं वहीं सरकार ठीक से काम कर रही है या नहीं, इससे जानने के हमें सूचना का अधिकार भी मिला हुआ है। यह अधिकार आमजन की लोकतंत्र में भागीदारी को सूनिश्चित करता है। गांव हो या शहर, छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाओं, गोष्ठियों और सेमिनारों के माध्यम के अलावा सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर आयोजित सेमिनारों और गोष्ठियों के माध्यम से भी लोगों को सूचना अधिकार एवं इसके प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। जागरूकता अभियान अभी भी जारी है। इसके साथ-साथ अब तक हजारों लोगों सूचना आवेदन लिखवाने में मदद की है। इन्होंने

स्वयं 500 से अधिक जनहित में सूचना आवेदन लगाए हैं। जिनमें मुख्य रूप से हरियाणा के एजूसेट सिस्टम, महिलाओं के लिए शहरों एवं कस्बों में सार्वजनिक शौचालय के सम्बन्ध में, मजदूरों के लिए लेबर सेस तथा उन्हें मिलने वाले लाभों के संदर्भ में, राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा के सम्बन्ध में, ईट-भटठों से निकलने वाली राख के सम्बन्ध में, मिलावटी सामान के बारे में, राज्य में साफ पीने के पानी के बारे में, कौशल रोजगार निगम की कार्यप्रणाली बारे, अमृत योजना, बीपीएल के लिए बनने वाले घरों के बारे में आदि ऐसी जानकारियां थी जिस पर सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के टायलेट, एजुसेट सिस्टम, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी का मुदा, कॉलेजों में प्राध्यापकों की कमी, टोल प्लाजा, स्कूलों में लड़कियों के लिए टायलेट की सुविधा इत्यादि।

इनका कहना है कि ज्यादा दिक्कत वहां पर आती है जहां ठेकेदार, नेता और अधिकारियों का गठजोड़ काम कर रहा हो। हालांकि जनहित की जानकारी में किसी अधिकारी, नेता या ठेकेदारा का व्यक्तिगत नुकसान नहीं होता लेकिन उनकी लूट की जानकारी जनता को हो जाती है और ऐसे मामले में यह गठजोड़ किसी सूचना आवेदक पर किसी भी हद तक दबाव डाल सकता है।

बेशक सूचना अधिकार कानून 2005 लागु हुआ। लेकिन सरकार ने इसके प्रचार -प्रसार के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। यूपीए सरकार ने इसमें कई बार संसोधन के नाम पर कमजोर करने की कोशिश की लेकिन जन दबाव के चलते सरकार ने अपने कदम वापिस खींच लिए। लेकिन 2014 के बाद केन्द्र सरकार ने इसमें कई बार संसोधन कर इसे कमजोर कर दिया है। वर्तमान केन्द्र सरकार की मंशा है कि और ज्यादा पंगु बना दिया जाए। केन्द्र सरकार के इन संसोधनों के खिलाफ जनता को सड़क पर आना होगा अन्य यह महत्वपूर्ण अधिकार कागजी बनकर रह जाएगा। सुभाष के अनुसार इस कानून ने गांव और कस्बों तक अपनी पैठ बनाई है। इसके प्रयोग करने वाले की तादाद भले ही कम हो, लेकिन इस कानून के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। गोपनीयता के जिस अभेद दुर्ग में शासन और सत्ता अपने कारनामों को अंजाम देते थे, इस कानून के जरिए उसमें दरारें पड़ने लगी हैं। सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष करने वालों की एक बड़ी जमात तैयार हुई है और उसमें हर रोज बढ़ौतरी हो रही है। अनुभव बताता है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूर लगेगा। असल में यह कानून भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं है। बल्कि आम जन की जनतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास है।

बलिदानियों ने दिखाई है राह, उन्हें आजादी से उड़ने की

सुनील कुमार महला

जगदंबा प्रसाद मिश्र ह्यहितैषीह्ल ने क्या खूब कहा है-ह्यशहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले,वतन पर मरनेवालों का यही बाकी निशाँ होगाह्ल भारतीय इतिहास में 26 जुलाई का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्यों कि यह वह दिन है, जब हम प्रत्येक वर्ष ह्यकारगिल विजय दिवसह्ल के रूप में मनाते हैं। वास्तव में यह हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, संकल्प, शौर्य और बलिदान की मिसाल है। यह हमारे देश के उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर है, जिन्होंने देश सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहूति दे दी थी। यदि हम यहां पर इस दिवस के मनाये जाने की बात करें तो पाठकों को बताता चलूं कि वर्ष 1999 में युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में उनका सम्मान करने के लिये इस दिवस को यानी कि 26 जुलाई को ह्यकारगिल विजय दिवसह्ल के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि साल 2000 में द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक की स्थापना भारतीय सेना द्वारा वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में बनाया गया था तथा बाद में वर्ष 2014 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले के द्रास शहर में स्थित होने के कारण इसे ह्यद्रास युद्ध स्मारकह्ल के रूप में भी जाना जाता है। बाद में, विभिन्न संघर्षों व मिशनों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को समर्पित ह्यराष्ट्रीय युद्ध स्मारकह्ल का उद्घाटन साल 2019 में किया गया। बहरहाल, पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि 3 मई 1999 को भारत-पाकिस्तान के बीच यह युद्ध तब शुरू हुआ, जब भारत को पता चला कि पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों और सैनिकों ने कारगिल के हाई अल्टीट्यूड (16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर) इलाकों पर कब्जा कर लिया है, ये जगहें भारतीय क्षेत्र में थीं और सामरिक दृष्टि से हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व अहम्‍ थीं।वास्तव में, वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध परमाणु संपन्न दक्षिण एशिया में पहला सैन्य संघर्ष/युद्ध था, जो दो परमाणु संपन्न देशों(भारत-पाकिस्तान) के बीच पहला वास्तविक युद्ध था। दरअसल, 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद, भारत-पाकिस्तान ने निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं पर सैन्य चौकियों के माध्यम से सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण की होड़ में निरंतर तनाव का सामना किया। इसके बाद 1998 में दोनों ही देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। इसके बाद फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा हुई। वास्तव में इसका उद्देश्य कश्मीर संघर्ष को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय रूप से हल करना था, लेकिन वर्ष 1998-1999 में ठंड के मौसम के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने कारगिल, लद्दाख के द्रास व बटालिक सेक्टर में एन एच 1ए पर स्थित किलेबंद ठिकानों पर कब्जा करने के लिये नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) के पार गुप्त रूप से सैनिकों को प्रशिक्षित और तैनात किया। भारत ने पाकिस्तान के इन घुसपैठियों को आतंकी और जिहादी समझा, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान का यह हमला उसका एक बहुत ही सुनियोजित सैन्य अभियान था। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि यह युद्ध वर्ष 1999 की गर्मियों में कारगिल सेक्टर में मश्कोह घाटी से लेकर तुरतुक तक फैली 170 किलोमीटर लंबी पर्वतीय सीमा पर लड़ा गया था और इसके प्रत्युत्तर में, भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरूआत की, जिसमें घुसपैठ का मुकाबला करने के लिये 200,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया था। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन(कारगिल युद्ध के दौरान) को ह्यऑपरेशन बद्रह्ल नाम दिया था, जिसका उद्देश्य कारगिल सेक्टर पर कब्जा करके श्रीनगर-लेह राजमार्ग को बाधित करना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से अलग करना था, लेकिन पाकिस्तान की यह साजिश ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए।भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए ह्यऑपरेशन विजयह्ल शुरू किया और 60 दिनों तक भारत पाकिस्तान के बीच चले इस युद्ध में 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान द्वारा सभी कब्जे वाले इलाकों को घुसपैठ से आजाद करा लिया। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना का ह्यऑपरेशन सफेद सागरह्ल तथा भारतीय नौसेना का ह्यऑपरेशन तलवारह्ल भी कारगिल युद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे।

यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर हुए उस युद्ध में हमारे 527 जवानों ने प्राणाहुति दी थी।

इस युद्ध में भारतीय सेना के वीरों ने ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली हवाएं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए अदम्य साहस, वीरता , शौर्य और दृढ़ता का परिचय दिया, इनमें लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय (परमवीर चक्र, मरणोपरांत), कैप्टन विक्रम बत्रा (परमवीर चक्र, मरणोपरांत),ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव (परमवीर चक्र) तथा राइफलमैन संजय कुमार(परमवीर चक्र) शामिल हैं। इन वीरों में सूबेदार मेजर (मानद कैप्टन) योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र (19 साल) में परमवीर चक्र से सम्मानित अदम्य साहस, शौर्य और वीरता की मिसाल हैं। बहरहाल, बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे कि कारगिल युद्ध के बाद ही हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का गठन सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच ह्यसंयुक्तताह्ल को बढ़ावा देने के लिये किया गया था। उल्लेखनीय है कि सीडीएस सरकार के एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है और तीनों सेवाओं के एकीकरण की देखरेख करता है। इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध के बाद सुरक्षा क्षेत्र में सुधार, त्रि-सेवा कमानों की स्थापना,तकनीकी खुफिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) की स्थापना,सीमा प्रबंधन एवं परिचालन सुधार, सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यासों, आतंकवाद विरोधी उपायों, स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की आवश्यकता तथा विभिन्न सैद्धांतिक परिवर्तनों जैसे सुधारों को बल मिला। कहना गलत नहीं होगा कि इस युद्ध ने हमारे देश की सैन्य रणनीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

सच तो यह है कि युद्ध ने देश में मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया और राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढाँचे में बड़े सुधारों को प्रेरित किया। इसने नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) को एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में फिर से स्थापित किया और ह्यकोल्ड स्टार्ट सिद्धांतह्ल जैसे नए सैन्य सिद्धांतों के विकास को गति दी। अंत में अज्ञात के शब्दों में यही कहूंगा कि-ह्यसैंकड़ों परिंदे आसमान पर आज नजर आने लगे, बलिदानियों ने दिखाई है राह, उन्हें आजादी से उड़ने की।

रास्ते और भी है

भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने संबंध सुधारने के लिए अन्य देशों के साथ-साथ अमेरिका की इतनी यात्रा नहीं की। अपने 11 साल के शासन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 11 बार अमेरिका गए उनकी और राष्ट्रपति ट्रंप की निकटतम मित्रता भारत में ही नहीं बल्कि जग जाहिर थी, फिर ऐसा क्या हो गया की दोनों लोकतांत्रिक देश के प्रमुखों में इतनी कटुता हो गई के ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाने और रूस से पेट्रोल मंगवाने पर पेनल्टी लगाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा क्या हो गया कि यह जानते हुए भी पाकिस्तान चीन के नजदीक है, भारत और पाकिस्तान में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में संघर्ष को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और पाकिस्तान के सेवा प्रमुख, आसिफ मुनीर को अमेरिका में लंच पर बुलाया यह जानते हुए कि भारत में पहलगाम में आतंकी त्रासदी के लिए वही आदमी जिम्मेदार है। इतना ही नहीं पाकिस्तान भारत सैनिक संघर्ष में चीन तथा तुरकिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका फर्स्ट इस नीति को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने अलग-अलग देश पर टैरिफ नीति के द्वारा आक्रमण किया जो देश ट्रंप की नीतियों का अनुसरण नहीं करते थे उन पर भारी टैरिफ लगा दिया, कनाडा ब्राजील यूरोपीय देश जापान चीन आदि ने ट्रंप को टैरिफ नीति को लेकर मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगा दिया, ट्रंप ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल तथा हथियार मंगवाता है। जिसकी सहायता से रूस यूक्रेन पर युद्ध धोंप? दिया जिसके कारण यूक्रेन में हजारों लोग मर रहे हैं पूछा जा सकता है कि अमेरिका भी तो रूस के साथ कई वस्तुओं का व्यापार कर रहा है तो भारत की तरह वह भी तो रूस की यूक्रेन के खिलाफ मदद कर रहा है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ न केवल कम कर दिया है बल्कि ट्रंप चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने के लिए अमेरिका भी जा रहे हैं। कुछ लोगों का यह सोचना है कि अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने और रूस के द्वारा भारत को तेल बेचने को लेकर पेनल्टी लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं लेकिन अमेरिका भारत को समय-समय पर परेशान करता रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी तथा वाजपेई के शासनकाल में जब हमने परमाणु परीक्षण किया तब भी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। भारत ने सभी स्थितियों का बहादुरी से मुकाबला किया। अब भी भारत ट्रंप की दादागिरी की हवा निकाल देगा, भारत रूस तथा चीन अगर आपस में मिल जाते हैं और ब्रिक्स देश अगर मिलजुल कर व्यापार करते हैं तो इससे विश्व में डॉलर का महत्व कम हो जाएगा।

भारत ने कुछ समय पहले इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है जो की भारत के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसमें भारतीय माल पर 95% कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारत को चाहिए की विश्व व्यापार संघ की सहायता से अन्य देशों के साथ भी इंग्लैंड की दर्ज पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। जो व्यापार अमेरिका के साथ हो रहा है और उसे पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने से बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए भारत छोटे-छोटे देशों में बाजार की तलाश करें और व्यापारिक समझौते करें, अमेरिका को

यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत पर टैरिफ लगाकर या भारतीय लोगों को अमेरिका में काम से निकाल कर भारत को नुकसान पहुंचेगा। इस सारे का अमेरिका पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

गाजा पर इजराइल के हमले में दो पत्रकारों सहित 5 की मौत, इजराइल ने एक पत्रकार को बताया हमास का आतंकी

तेल अवीव। गाजा पर इजराइल के ताजा हमले में अल-जजीरा के दो पत्रकारों के साथ पांच लोगों की मौत हो गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हमले में मारे गए एक पत्रकार अनस अल शरीफ को हमास का आतंकी बताया है। दी येरुशलम पोस्ट के मुताबिक गाजा के अल-शिफा अस्पताल के पास इजराइल के ताजा हमले में दो पत्रकारों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। इनमें अल जजीरा के काम करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार अनस अल शरीफ भी शामिल हैं। हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने बयान जारी कर दावा किया है कि अनस अल-शरीफ हमास के आतंकी सेल के प्रमुख के रूप में काम कर चुका था और इजराइली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ रॉकेट हमलों को आगे बढ़ाने में शामिल था।

नेतन्याहू ने गाजा में विदेशी पत्रकारों को अनुमति देने की योजना की घोषणा की

यरुशलम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के दौरान गाजा में अधिक विदेशी पत्रकारों को सेना के साथ रिपोर्टिंग करने की अनुमति देने की योजना की भी घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर गाजा में जीत की अपनी रूपरेखा भी पेश की। हमास के खिलाफ 22 महीने से जारी युद्ध के दौरान गाजा में प्रवेश पर कड़ी पाबंदियां लगी रही हैं। 07 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह के हमले के बाद से इजराइल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अधिकांश विदेशी पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से गाजा में जाने से रोका है। अब तक कुछ चुनिंदा मीडियों को इजराइली सेना ने सुरक्षा अधिकारियों की सख्त निगरानी में पत्रकारों को एंबेड मिशनों पर गाजा ले गए हैं। नेतन्याहू ने कहा, हमने निर्णय लिया है और सेना को निर्देश दिया है कि विदेशी पत्रकारों को, बहुत से विदेशी पत्रकारों को, गाजा में लाया जाए। उन्होंने यह भी जोड़ा, सुरक्षा सुनिश्चित करने में समस्या है, लेकिन मेरा मानना है कि यह जिम्मेदारी और सावधानी के साथ, आपकी सुरक्षा बनाए रखते हुए यह किया जा सकता है।हालांकि, प्रधानमंत्री ने इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की।

गाजा सिटी पर कब्जे की इजराइली योजना पर यूरोपीय देशों का कड़ा विरोध

मैड्रिड। स्पेन सहित आठ यूरोपीय देशों ने इजराइल की गाजा सिटी पर कब्जे की योजना को लेकर कड़ा विरोध जताया है। इन देशों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत हो सकती है और लगभग दस लाख फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित होना पड़ सकता है। दरअसल, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा सिटी पर नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद इजराइल के भीतर और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। आठों देशों के विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में कहा है कि यह निर्णय मानवीय संकट को और गहरा करेगा और शेष बंधकों के जीवन को और अधिक खतरे में डालेगा। बयान में अनुमान जताया गया कि इस अभियान से अस्वीकार्य स्तर पर नागरिक मौतें होंगी और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर होंगे। विदेश मंत्रियों ने यह भी कहा कि गाजा सिटी पर कब्जा और सैन्य नियंत्रण, दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में एक «बड़ा अवरोध» साबित होगा, जो ही व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का एकमात्र मार्ग है। इस बयान पर स्पेन के अलावा आइसलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्लोवेनिया ने हस्ताक्षर किए हैं।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इजराइल के कुछ सहयोगी देशों सहित कई शक्तियां बंधकों की रिहाई और गाजा में मानवीय संकट को कम करने के लिए वार्ता के जरिए युद्धविराम की अपील कर रहे हैं।

लंदन में इजराइली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर मार्च, मध्य पूर्व तनाव ने बढ़ाई ब्रिटेन में हलचल

लंदन। गाजा युद्ध के बीच ब्रिटेन में बढ़ते तनाव के माहौल में लंदन के मध्य क्षेत्र में इजराइली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर लोगों ने मार्च किया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक रैली निकालने की योजना के साथ आगे बढ़े। मार्च में हिस्सा लेने वालों में नोआ गुटमैन भी शामिल थीं, जो 24 वर्षीय बंधक एव्यातर डेविड की चचेरी बहन हैं। डेविड को पिछले सप्ताह हमास द्वारा जारी एक वीडियो में दिखाया गया था, जिसमें वे गाजा की सुरंग में अपना ही कब्रगाह खोदते हुए बेहद कमजोर हालत में नजर आए। इस वीडियो ने इजराइल में गुस्सा भड़का दिया था। उल्लेखनीय है कि 07 अक्टूबर 2023 को हमास-नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने इजराइल पर हमले के दौरान 251 लोगों को अगवा किया था। इनमें से करीब 50 अब तक रिहा नहीं हुए हैं और अनुमान है कि 20 जीवित हैं।

इजराइल ने पिछले सप्ताह गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना की घोषणा की थी, जिसे युद्ध समाप्त करने और बंधकों को छुड़ाने की रणनीति का हिस्सा बताया गया। हालांकि, बंधकों के परिजन और कई अंतरराष्ट्रीय नेता इस योजना की आलोचना कर चुके हैं, उनका कहना है कि इससे और खून-खराबा होगा और बंधकों की जान पर खतरा बढ़ेगा।

काबुल में पानी का संकट गहराया, जिला 13 सबसे अधिक प्रभावित

एजेंसी

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पानी का संकट गहरा गया है। राजधानी का जिला 13 सबसे अधिक प्रभावित है। यहां सुबह से शाम तक लोग पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं। बचे-खुचे जल स्रोतों पर बच्चे-बूढ़े-जवानों की लंबी कतार लगी रहती है। तुलूअ न्यूज के अनुसार जिला 13 के निवासियों के लिए जिंदगी एक चुनौती बन गई है। हर किसी को पीने के पानी की एक घूंट की तलाश में सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। सुबह से ही कतारें लग जाती हैं। हर कोई पानी खत्म होने से पहले अपने परिवार के लिए थोड़ा-बहुत पेयजल घर ले जाने की उम्मीद करता है। जिला 13 के निवासी यार मोहम्मद ने कहा, मैं हर रोज पांच बैरल पानी खरीदता हूं। पानी की खपत बहुत अधिक है। 1000 लीटर के पानी के एक बैरल की कीमत 1.1 डॉलर चुकानी पड़ रही है। इसी जिले के बशीर अहमद ने कहा, हम पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं। सरकार से हमारी विनती है कि वह इस ओर ध्यान दे। इस इलाके के एक नाबालिग लड़के मोहम्मद फैज ने कहा, मैं सुबह जल्दी आता हूं और 11 बजे तक पानी की व्यवस्था करता हूं। कभी हमारे बैरल भरे होते हैं, कभी खाली रहते हैं। पानी की समस्या पर जल प्रबंधन विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और देश के नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। जल विशेषज्ञ नजीब रहमान सादीद ने कहा, पंजशीर जलग्रहण क्षेत्र से पानी स्थानांतरित करने जैसी परियोजनाएं मददगार हो सकती हैं। बगदरा बांध का काम जल्द पूरा होना चाहिए। ऊर्जा और जल मंत्रालय के प्रवक्ता मतिउल्लाह आबेद ने कहा, मंत्रालय की शाह वा एरोस बांध से काबुल तक पानी पहुंचाने की योजना है। इस्लामिक अमीरात की कैबिनेट ने प्रशासनिक कार्यालय के नेतृत्व में एक समिति गठित की है। इसमें संबंधित विभाग शामिल हैं और तकनीकी कार्य शुरू हो गया है। काबुल शहर को 22 जिलों में बांटा गया है। जिला 13 उनमें से एक है। तालिबान के काबुल के पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत जिला 13 में अनौपचारिक बस्तियों को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया था।

यूनुस शासन में बांग्लादेश चरमपंथी और सांप्रदायिक ताकतों से तबाह हो रहा हैः अवामी लीग

एजेंसी

ढाका। अवामी लीग ने सोमवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने कहा कि देश इस समय चरमपंथी, सांप्रदायिक और आतंकवादी ताकतों के साथ ही विदेशी एजेंटों की खतरनाक गतिविधियों से गंभीर खतरे और तबाही की स्थिति में है। पार्टी ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटपर काबू पाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में 21 मांगें पेश की गई हैं।

भयानक संकट की ओर इशारा करते हुए पार्टी ने कहा कि बांग्लादेश, जिसे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में हुए मुक्ति संग्राम के बाद बनाया गया था, आज चरमपंथी, सांप्रदायिक और आतंकवादी ताकतों के हमलों से बुरी तरह प्रभावित है।

पार्टी ने कहा कि देश अब संकट में है और युद्ध के मैदान जैसी स्थिति में पहुंच चुका है- घायल और खून से लथपथ जमीन बन गया है। अवामी लीग ने कहा, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, मानवाधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, मीडिया की आजादी छिन ली गई है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हमले और बलात्कार जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आम लोगों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है।

तुर्की में 6.1 तीव्रता का भूकंप, एक व्यक्ति की मौत

एजेंसी

इस्तांबुल। तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत बालिकेसिर में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (एएफएडी) के अनुसार, यह भूकंप रविवार शाम 7 बजकर 53 मिनट पर सिंदिरगी जिले में आया। गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि 81 साल के एक बुजुर्ग को बचाने के बाद उनकी मौत हो गई। कई लोग घायल हुए और 15 से ज्यादा इमारतें गिर गईं। एनटीवी प्रसारक पर दिखाए गए फुटेज में मलबे में तब्दील एक इमारत दिखाई दे रही है, जिसके मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। समाचार एजेंसी के अनुसार, मंत्री येरलिकाया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि यह झटका इस्तांबुल और आसपास के इलाकों में भी महसूस हुआ। इसके बाद एएफएडी और सभी संबंधित एजेंसियों ने तुरंत मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा, «फिलहाल, किसी भी प्रतिकूल स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं है, और हम घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। तुर्की मीडिया द्वारा प्रसारित तस्वीरों के अनुसार, भूकंप के बाद बालिकेसिर प्रांत में कई इमारतें ढह गईं। इससे पहले, 3 अगस्त को भी प्रशांत महासागर में रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर 6.8 तीव्रता का झटका महसूस किया गया था। यह भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजकर 37 मिनट पर आया था। यह क्षेत्रीय राजधानी पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 277 किलोमीटर दूर, 26 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र (जीएफजेड) के अनुसार, इससे पहले रूस के कुरील द्वीप समूह में 7 की तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी और पुष्टि की है कि भूकंप के बाद कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की गई थी। यह भूकंप कुरील द्वीप समूह के पूर्व में रात दर्ज किए गए 6.2 तीव्रता के एक और भूकंप के बाद आया था। यह भूकंपीय गतिविधि 30 जुलाई को आए 8.7 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद हुई थी, जो अब तक दुनिया भर में दर्ज किए गए छठे सबसे शक्तिशाली भूकंप के बराबर है।

पाकिस्तान में 22 दिन से खुंजेराब दर्रे के रास्ते चीन के बीच व्यापार और यात्रा बाधित

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के गिलगित-बाल्तिस्तान के काराकोरम राजमार्ग (केकेएच) पर चल रहे धरने के कारण लगातार 22वें दिन खुंजेराब दर्रे के रास्ते पाकिस्तान और चीन के बीच यात्रा और व्यापार बाधित रहा। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध जारी है।

नींद से जागी संघीय सरकार ने समस्या के समाधान के लिए आनन-फानन में सोमवार को बैठक आहूत की है। डान अखबार की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संघीय समिति का गठन किया है। समिति इस मुद्दे के समाधान के लिए आज बैठक करेगी। गिलगित-बाल्तिस्तान के मुख्यमंत्री हाजी गुलबर खान, मुख्य सचिव अबरार अहमद मिर्जा, पीपीपी अध्यक्ष अमजद हुसैन एडवोकेट, पूर्व मुख्यमंत्री और पीएमएल-एन अध्यक्ष हफीजुर रहमान को भी समिति में शामिल किया गया है। ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी के विरोध प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान और चीन के बीच व्यापार और यात्रा, साथ ही सोस्ट ड्राई पोर्ट पर व्यावसायिक गतिविधियां पिछले 22 दिनों से बंद हैं। ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी आहूत विरोध प्रदर्शन को व्यापारिक संगठनों, स्थानीय सरकार, विपक्षी दलों और क्षेत्र के धार्मिक समूहों का समर्थन प्राप्त है। इस मामले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री हाजी गुलबर खान के प्रसास से गठित एक समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से मुलाकात की। उन्होंने मुद्दों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सिफारिशें तैयार कीं। प्रदर्शनकारियों ने समिति को दो सूत्री एजेंडा दिया है। उन्होंने खुंजेरब दर्रे के माध्यम से चीन से आयातित वस्तुओं पर राज्य के निवासियों को आयकर, बिक्री कर और अन्य संघीय करों से छूट और एकमुश्त माफी योजना की मांग की है।

पाकिस्तान से एक दिन में 300 परिवार और 350 कैदी अफगानिस्तान भेजे गए

एजेंसी

काबुल। पाकिस्तान से एक दिन में 300 परिवारों और 350 कैदियों को अफगानिस्तान भेजा गया है। पाकिस्तान से निर्वासित किए गए इन लोगों की पीड़ा यह है कि उनका सारा सामान वहीं छूट गया है। अफगानिस्तान पहुंचे इन लोगों को उनके संबंधित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है। अफगानिस्तान के तुलूअ न्यूज के अनुसार, नांगरहार के अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक सहायता प्रदान करने के बाद निर्वासित लोगों को उनके गृह क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। तोरखम में प्रवासी परिवहन प्रमुख बख्त जमाल गोहर ने कहा, पिछले 24 घंटों में 300 परिवारों को वापस भेजा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 350 कैदियों को हमें सौंपा है। इनमें निर्वासित लोगों के 20 परिवार शामिल हैं। इनके पास कानूनी दस्तावेज भी हैं। इन प्रवासियों और निर्वासित लोगों को परिवहन समिति ने उनके संबंधित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया है। बख्त जमाल गोहर ने कहा कि कुछ निर्वासित व्यक्ति इस्लामिक अमीरात और अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों से अधिक सहायता प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान से निर्वासित एजाजुल हक ने कहा, हमारा सारा सामान वहीं छूट गया। मैं अपने साथ केवल एक गद्दा और एक बिस्तर लाया था। एक अन्य निर्वासित शरबत खान ने कहा, 40 साल बाद हम अपने वतन लौट आए हैं। हम खुश हैं, लेकिन सहायता के अलावा हमें जमीन भी चाहिए। बताया गया है कि कुनार के नारी जिले के 50 वर्षीय निवासी अब्दुल्ला को तीन दशक तक पाकिस्तान में रहने के बाद जबरन निर्वासित किया गया है। उनके तीन विकलांग बेटे हैं और उन्हें आठ दिन पहले पाकिस्तान पुलिस ने निर्वासित किया है। अब्दुल्ला ने कहा, मैं मजदूरी कर रहा था। वे अचानक आए, मुझे गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया। मेरे तीन बच्चे विकलांग हैं और बाकी तीन स्वस्थ हैं। उन्हें भी कल निर्वासित कर दिया गया। अब्दुल्ला के बेटे शरीफुल्लाह ने कहा, हमें अपने पिता के बारे में कोई खबर नहीं थी। हमने थानों के चक्कर लगाए, तब पता चला कि हमारे पिता को निर्वासित कर दिया गया है।

पाकिस्तान के वजीरिस्तान में सैनिकों पर हमला, एक जवान की मौत, जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में सैनिकों की टुकड़ी पर घात लगाकर किए गए हमले में एक जवान की मौत हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। डान अखबार की वेबसाइट में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह खबर आज सुबह प्रसारित की गई। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, सैनिकों की टुकड़ी उत्तरी वजीरिस्तान के शावल मर्दाह इलाके से ऊपरी दक्षिणी वजीरिस्तान के सिरनाराई इलाके में आगे बढ़ रही थी। तभी घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस गोलीबारी में जवान नवीद की मौत हो गई। नायक अमजद, सिपाही अबू बकर, सिपाही सियाम, सिपाही नासिर और सिपाही शौकत घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान की सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने अभी तक इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है। घायल जवानों को इलाज के लिए रजमाक स्थित एक सैन्य केंद्र में पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार, इलाके में सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर की गोलीबारी में मारे गए युवक के रिश्तेदारों पर मुकदमा

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थानीय पुलिस ने 18 जुलाई को फ्रंटियर कोर (एफसी) की कथित गोलीबारी में मारे गए युवक की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन के सिलसिले में अब पीड़ित रिश्तेदारों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। रिश्तेदारों ने चगाई में विरोध प्रदर्शन कर अंतिम संस्कार वाहन के चालक शाह डार की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी। द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर में दावा किया गया है कि 18 जुलाई को शाह डार पुत्र अमानुल्लाह की चगाई जिले के नोकुंडी इलाके में एफसी की गोलीबारी में मौत हो गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और शाह डार के के परिवार व रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया था। शव को बाब उमर चौक पर रख कर जाम लगा दिया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि युवक की हत्या में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस ने बल के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस और एफसी पर हमले के आरोप में मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने मामले में कई लोगों को नामजद किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 18 जुलाई को शाह डार की मौत के बाद एफसी ने उसके शव को अपने कब्जे में ले लिया था। परिजनों को शव के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह विरोध प्रदर्शन इसी वजह से हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर हवा में गोलियां भी चलाईं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई थी।

आईडीएफ ने आतंकवाद के आरोप में एक पत्रकार की हत्या की, कहा, 'प्रेस बैज आतंकवाद के लिए ढाल नहीं है'

एजेंसी

यरूशलम। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने सोमवार को पुष्टि की कि गाजा में एक हमले में अल जजीरा के पत्रकार अनस अल-शरीफ की मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वह 'हमास में एक आतंकवादी सेल का प्रमुख' था और चेतावनी दी कि 'प्रेस आतंकवाद के लिए ढाल नहीं है।' अल-शरीफ अपने साथियों, इब्राहिम जहीर, मोमेन अलीवा और मोहम्मद नौफल, के साथ मारा गया। एक बयान में, सेना ने कहा, «अल-शरीफ हमास के एक आतंकवादी समूह का प्रमुख था, और उसने इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर रॉकेट हमले किए थे। गाजा से मिली खुफिया जानकारी और दस्तावेज में रोस्टर, टेररिस्ट ट्रेनिंग लिस्ट और वेतन रिकॉर्ड शामिल हैं। यह साबित करते हैं कि वह अल जजीरा से जुड़ा एक हमास कार्यकर्ता था। आईडीएफ ने आगे कहा कि अक्टूबर में उसने गाजा में जब्त की गई सामग्री प्रकाशित की थी, जिससे अल-शरीफ के हमास से सैन्य संबंध की स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई थी। सेना ने आगे कहा, ये दस्तावेज एक बार फिर उसकी आतंकवादी गतिविधि की पुष्टि करते हैं, जिसे अल जजीरा ने नकारने की कोशिश की। इजरायली सेना ने कहा कि जब्त किए गए दस्तावेजों में कर्मियों की टेबल्स, टेररिस्ट ट्रेनिंग कोर्स की लिस्ट, टेलीफोन डायरेक्टरी और सैलरी रिकॉर्ड शामिल हैं, जो स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि वह गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन के लिए एक आतंकवादी के रूप में काम करता था। उन्होंने दावा किया कि इन दस्तावेज़ों से यह भी पता चलता है कि आतंकवादी का कतर के मीडिया नेटवर्क अल जज़ीरा में जुड़ाव था। इजरायल ने कहा कि हमले से पहले, नागरिक हताहतों की संख्या कम करने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल, हवाई निगरानी और अतिरिक्त खुफिया आकलन जैसे उपाय किए गए थे। अल-शरीफ अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और गाजा में इजरायली बमबारी के बारे में एक्स पर पोस्ट कर रहे थे। उनकी मौत की खबर आने के बाद, उनके सहयोगियों ने उनके अकाउंट से एक पहले से लिखा हुआ संदेश पोस्ट किया, जिसमें लिखा था: अगर मेरे ये शब्द आप तक पहुँचें, तो जान लें कि इजरायल मुझे मारने और मेरी आवाज़ को खामोश करने में कामयाब हो गया है।

अमेरिकी धरती से पाकिस्तानी सेना प्रमुख की भारत को परमाणु बम की गीदड भभकी

एजेंसी

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और स्वयंभू फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी है। मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और फ्लोरिडा के टाम्पा स्थित ग्रैंड हयात होटल में एक डिनर के दौरान उन्होंने यह विवादित बयान दिया। डिनर में मौजूद पाकिस्तानी कारोबारी अदनान असद और अन्य मेहमानों के सामने मुनीर ने कहा कि यदि भारत के साथ जंग में पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आया, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सिंधु नदी भारतीयों की खानदानी संपत्ति नहीं है और पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। मुनीर ने आरोप लगाया कि भारत ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर 25 करोड़ लोगों को भूख और प्यास के खतरे में डाल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान भारत के बांध बनने का इंतजार करेगा और जब बांध तैयार हो जाएगा, तब उसे मिसाइलों से उड़ा देगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत पर किसी भी तरह का परमाणु हमले की धमकी से डरने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय संसद और अनेक मंचों से बार बार दोहरा चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है।

शेख हसीना सहित 47 लोगों के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में अधिकारियों के बयान दर्ज

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश के तीन अधिकारियों ने राजुक पुर्बाचल न्यू टाउन परियोजना के भूखंडों के आवंटन में धांधली को लेकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित 47 लोगों के खिलाफ दायर तीन मामलों में आज अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। इसके बाद कोर्ट ने तीनों मामलों की सुनवाई 26 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के उप निदेशक सलाहुद्दीन, सहायक निदेशक अफनान जन्नत केया और एसएम रशीदुल हसन के बयान ढाका विशेष न्यायाधीश कोर्ट-5 में दर्ज किए गए। न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने इसके बाद तीनों मामलों की सुनवाई 26 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने 31 जुलाई को इन मामलों में आरोप तय करते हुए आरोपितों के फरार होने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए थे। इस अदालत के अलावा ढाका विशेष न्यायाधीश कोर्ट-4 ने 31 जुलाई को इसी संबंध में दर्ज तीन अन्य मामलों में आरोप तय किए थे। 20 जुलाई को ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने मामलों को विशेष न्यायाधीश की अदालत में भेजा था। इससे पहले पहली जुलाई को अदालत ने इन मामलों में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय सहित 100 लोगों को तलब करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित करने का आदेश दिया था।एसीसी ने 12 जनवरी से 14 जनवरी तक छह मामले दर्ज किए हैं। संबंधित जांच अधिकारियों ने 10 मार्च को आरोप पत्र दाखिल किए। एसीसी के उप निदेशक मोहम्मद सलाहुद्दीन ने 14 जनवरी को शेख हसीना समेत आठ लोगों के खिलाफ पूर्वाचल न्यू टाउन परियोजना में 10 कट्ठा प्लॉट आवंटित करने में सत्ता का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज कराया। जांच अधिकारी और एसीसी की सहायक निदेशक अफनान जन्नत केया ने 10 मार्च को कुल 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एसीसी के सहायक निदेशक एसएम रशीदुल हसन ने इसी सिलसिले में 10 मार्च को शेख हसीना और उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय समेत 15 लोगों के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज कराया। उन्होंने 10 मार्च को 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एसीसी के उप निदेशक मोहम्मद सलाहुद्दीन ने 13 जनवरी को शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना, रेहाना के बेटे रदवान मुजीब सिद्दीक और बेटियों ट्यूलिप सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक समेत 15 लोगों के खिलाफ राजुक से प्लॉट हासिल करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का एक और मामला दर्ज कराया। बाद में एसीसी ने 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एसीसी ने उसी दिन शेख हसीना, ट्यूलिप सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक सहित 16 लोगों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। बाद में एसीसी ने 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उसने 13 जनवरी को रादवान मुजीब सिद्दीक और 15 अन्य के खिलाफ भी एक और मामला दर्ज किया। इस मामले में एसीसी ने 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एसीसी की सहायक निदेशक अफनान जन्नत केया ने 12 जनवरी को शेख हसीना और साइमा वाजेद पुतुल सहित 16 लोगों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। एसीसी ने इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

पटेल रिटेल लिमिटेड का आईपीओ 19 अगस्त को खुलेगा, प्राइस बैंड 237-255 रुपये प्रति शेयर

मुंबई/नई दिल्ली। सुपरमार्केट श्रृंखला पटेल रिटेल लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) निवेशकों के लिए 19 अगस्त को खुलकर 21 अगस्त को बंद होगा। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 237-255 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने जारी एक बयान में बताया कि निवेशक इसमें 21 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। वहीं, बड़े (एंकर) निवेशकों के लिए बोली की लगाने की प्रक्रिया 18 अगस्त को होगी। इसके लिए मूल्?य का दायरा (प्राइस बैंड) 237-255 रुपये प्रति शेयर तय किया है। निवेशक कम से कम 58 इक्विटी शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं, और इसके बाद 58 के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है। पटेल रिटेल लिमिटेड के 10 रुपये फेस वैल्यू वाले इस आईपीओ के तहत 85.18 लाख नए शेयर और प्रवर्तकों के 10.02 लाख शेयरों की बिक्री होगी। प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर्स ये शेयर बेचेंगे। इसमें पात्र कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन भी शामिल है। इसमें कर्मचारियों को आईपीओ में 20 रुपये प्रति शेयर की छूट दी जाएगी। कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों में से 59 करोड़ रुपये तक का इस्तेमाल पटेल रिटेल लिमिटेड के कुछ कर्जों का पूरा या आंशिक भुगतान/पूर्व-भुगतान के लिए करेगी।

बैंक बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए स्वतंत्र : आरबीआई गवर्नर

नई दिल्ली/मेहसाणा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंक बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। मल्होत्रा ने कहा कि यह आरबीआई के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आरबीआई के गवर्नर ने गुजरात के मेहसाणा जिले की गोजरिया ग्राम पंचायत में आयोजित वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियानपर एक समारोह में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही। मल्होत्रा ने एक निजी क्षेत्र के बैंक की ओर से बचत खातों के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष राशि बढ़ाने के बारे में पूछे जाने पर कहा, आरबीआई ने यह निर्णय प्रत्येक बैंक पर छोड़ दिया है कि वे कितना न्यूनतम शेष निर्धारित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बैंकों ने बचत खातों के लिए 10,000 रुपये न्यूनतम शेष राशि रखा है, जबकि कुछ ने 2,000 रुपये रखा है। वहीं, कुछ बैंकों ने (ग्राहकों को) इसकी छूट दी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह (आरबीआई के) नियामक क्षेत्राधिकार में नहीं है। इससे पहले बैंकिंग हितधारकों की पैरोकारी करने वाली एक नागरिक संस्था ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर आईसीआईसीआई बैंक के बचत खातों में न्यूनतम जमा राशि बढ़ाने का विरोध किया था। नागरिक संस्था बैंक बचाओ देश बचाओ मंच ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में आईसीआईसीआई बैंक के इस फैसले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में 1 अगस्त से खोले जाने वाले नए बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को पांच गुना बढ़ा दिया था।

अडानी डिफेंस एमआरओ सेवा प्रदाता इंडैमर टेक्निक्स का करेगी अधिग्रहण

अहमदाबाद। अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एडीएसटीएल) ने निजी क्षेत्र की एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग) सेवा प्रदाता कंपनी इंडैमर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड (आईटीपीएल) में शत-प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निर्णायक समझौता किया है। अडानी डिफेंस ने बताया कि उसने अपनी इकाई होराइजन एयरो सॉल्यूशंस लिमिटेड के माध्यम से और प्राइम एयरो सर्विसेज एलएलपी के साथ साझेदारी में यह समझौता किया है। होराइजन अभी अडानी डिफेंस और इंडैमर टेक्निक्स के निदेशक प्रजय पटेल के स्वामित्व वाली कंपनी प्राइम एयरो के बीच 50-50 की साझेदारी वाला संयुक्त उद्यम है। नागपुर में मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में रणनीतिक रूप से स्थित आईटीपीएल ने 30 एकड़ की भूमि पर एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड सुविधा स्थापित की है। इस सुविधा में 10 हैंगरों में 15 विमान के रखने की क्षमता है। आईटीपीएल को भारत के विमानन नियामक डीजीसीए, अमेरिकी नियामक एफएए और अन्य वैश्विक नागरिक उड्डयन नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी प्रमुख भारतीय और वैश्विक ग्राहकों को लीज रिटर्न चेक, हेवी सी-चेक, स्ट्रक्चरल रिपेयर और एयरक्राफ्ट पेंटिंग सहित एमआरओ सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है।

सोने पर टैरिफ को लेकर ट्रंप ने अटकलों पर लगाया विराम, दिया बड़ा बयान

वाशिंगटन। सोने पर संभावित टैरिफ को लेकर चल रही अटकलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विराम लगा दिया है। उन्होंने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का फिलहाल सोने पर टैरिफ लगाने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि सरकार चीन से आने वाले सोने पर भारी शुल्क लगाने की योजना बना रही है। इस खबर के बाद सोने के वैश्विक बाजार में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया था, लेकिन ट्रंप के इस स्पष्टीकरण से बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है और वह इस बाजार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। उनका यह बयान निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

संसद ने मणिपुर बजट और राज्य जीएसटी संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

एजेंसी

नई दिल्ली। संसद ने मणिपुर बजट तथा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने मणिपुर के बजट और संबंधित (संख्या 2) विधेयक, 2025 तथा मणिपुर जीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर संयुक्त चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इन्हें लोकसभा को लौटा दिया दिया। लोकसभा इन्हें पिछले हफ्ते पहले ही पारित कर चुकी है।केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्?यसभा में इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर, उसका बजट, उसका कर राजस्व, जीएसटी में उसकी भागीदारी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीतारमण ने कहा कि पहले राज्य के लिए लेखा अनुदान लाया गया था, लेकिन यह पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने पहले मणिपुर के मामले में बहुत रुचि दिखाई थी,

लेकिन आज जब मणिपुर के लोगों को उनका पैसा मिलने जा रहा है, तो उन्हें (विपक्ष को) इसकी अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से चर्चा में भाग लेने को कहा। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के लिए 2898 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। इसमें से 1667 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में व्यय होंगे, जिसका अर्थ है कि परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और रोजगार का सृजन होगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। सीतारमण ने कहा कि 1231 करोड़ रुपये राजस्व सहायता पर व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास में जो तत्काल जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए 523 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे पहले केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 और मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 दोनों विधेयकों को एक साथ राज्यसभा में विचारार्थ और वापसी के लिए प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने बजट (मणिपुर), 2025-26 को भी चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। राज्यसभा ने इन विधेयकों मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 और मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 लौटा दिया।

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक, 2025 पेश किया

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए आयकर विधेयक, 2025 का संशोधित संस्करण पेश किया। इस विधेयक में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल हैं, जो मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया था, जिसे 13 फरवरी को लोकसभा में मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर वित्त मंत्री ने पेश किया था। संशोधित आयकर विधेयक, 2025 में भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया हैं। प्रवर समिति ने आयकर विधेयक के लिए 285 सुझाव दिए थे। आयकर विधेयक, 2025 को भारत की कराधान प्रणाली को अद्यतन और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 60 वर्षों से अधिक समय से लागू

कानूनों की जगह लेगा। इसमें एक संशोधित संरचना, डिजिटल कराधान के प्रावधान, विवादों के समाधान की प्रणालियां और तकनीकी एवं डेटा-संचालित तरीकों के जरिए कर संग्रह का विस्तार करने की पहल शामिल है।

हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री, मजबूत लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 70 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 117 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 115 रुपये के स्तर पर हुई। इस तरह स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के साथ ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को करीब 67 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिल गया। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर उछल कर 122.84 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 75 प्रतिशत से अधिक का मुनाफ हो चुका है। हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर का 130 करोड़ रुपये का आईपीओ 5

से 7 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 316.64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 432.71 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 473.10 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 164.48 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 97.52 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 46.40 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है।

लोकसभा ने नए आयकर विधेयक को किया पारित

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा ने संशोधित नया आयकर विधेयक- 2025 और कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक- 2025 को पारित कर दिया है। केंद्रीय वित्?त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका संशोधित संस्करण पेश किया, जिसके तुरंत बाद आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी गई। ये विधेयक मौजूदा 1961 आयकर अधिनियम का स्थान लेने वाला है। यह विधेयक अब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले राज्यसभा में जाएगा। यह नया आयकर कानून 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। आइए जानते हैं इसके कानून बन जाने से करदाताओं को क्या-क्या लाभ होगा। वित्त मंत्री ने भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की करीब सभी सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित आयकर विधेयक- 2025 पेश किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कानूनों को समेकित और संशोधित करना है। इसके साथ ही लोकसभा ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक- 2025 को पारित कर दिया है, जिससे एकीकृत पेंशन योजना के अंशदाताओं को कर छूट प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन का रास्ता आसान होगा।लोकसभा में पारित संशोधित नए आयकर विधेयक, 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे। इसमें पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिससे कर कानून को समेकित और सरल बनाया जाएगा। इसमें 23 अध्यायों में 536 धाराएं भी होंगी, जो 800 से अधिक धाराओं से एक महत्वपूर्ण कमी है। इस कानून में स्पष्टता में सुधार, प्रारूपण में सुधार, वाक्यांशों को सरेखित करने और परस्पर संदर्भों को बेहतर बनाने के लिए प्रवर समिति की 285 सिफ़ारिशें (32 प्रमुख परिवर्तनों सहित) शामिल हैं। मानव हस्तक्षेप को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मूल्यांकन और अनुपालन प्रक्रियाएं फेसलेस और डिजिटल-प्रथम होंगी। कर अधिकारियों को कार्रवाई करने से पहले पूर्व सूचना जारी करनी होगी व प्रतिक्रियाओं पर विचार करना होगा। बिना किसी जुर्माने के आईटीआर की समय सीमा के बाद भी टीडीएस रिफंड की अनुमति देता है और गैर-देय करदाताओं के लिए अग्रिम शून्य-टीडीएस प्रमाणपत्रों का प्रावधान करता है। गृह संपत्ति आय: अब धाराएं स्पष्ट करती हैं कि नगरपालिका करों में कटौती के बाद 30 फीसदी की मानक कटौती लागू होती है और किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए निर्माण-पूर्व ब्याज की अनुमति है, पांच वर्षों में ब्याज की अनुमति है। इसके अलावा परिवर्तित पेंशन (एलआईसी पेंशन फंड या एनपीएस जैसी विशिष्ट पेंशन योजनाओं से एकमुश्त भुगतान): अब पूरी तरह से कर-कटौती योग्य, पिछली अस्पष्टताओं का समाधान शामिल है।

बीएसएनएल ने 5जी और डिजिटल तकनीकों में कौशल विकास के लिए वैश्विक कंपनियों से समझौता किया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने चार वैश्विक तकनीकी कंपनियों एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज इंक., सिस्को सिस्टम्स और नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में आयोजित हुआ।

इन समझौतों का उद्देश्य भारत के डिजिटल परिवर्तन को तेज करना और कौशल विकास तंत्र को मजबूत बनाना है। इसके तहत बीएसएनएल के जबलपुर स्थित शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, भारत रत्न भीमराव आंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग (बीआरबीआरएआईटीटी) में

5जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग और डिजिटल तकनीकों में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

यह पहल दूरसंचार विभाग (डीओटी) की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत बीआरबीआरएआईटीटी में टेलीकॉम इनोवेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (टीआईआरटीसी) स्थापित किया जाएगा। इसे उद्योग-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण पर केंद्रित होगा। यह केंद्र प्रधानमंत्री के 'स्किल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, दूरसंचार सचिव डॉ. नीरज मित्तल, बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी और भागीदार कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। समझौते पर बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक ए. रॉबर्ट जे. रावी ने हस्ताक्षर किए। उनके साथ नोकिया इंडिया के कंट्री हेड तरुण छाबड़ा, सिस्को के एमडी हरीश कृष्णन, एरिक्सन इंडिया के एमडी नितिन बंसल और क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष सवी सोनी शामिल थे।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया। मंत्री रेड्डी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करेगा।

संसद में पेश खनन कानूनों में संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राज्य वित्त पोषण को सक्षम बनाना है। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों सहित बेहद जरूरी खनिजों की निरंतर और बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जो परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अभी इन खनिजों की आपूर्ति शृंखला पर मुख्य रूप से चीन का प्रभुत्व है।

सर्राफा बाजार में गिरावट जारी, सोना और चांदी की घटी कीमत

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज गिरावट का रुख नजर रहा है। सोना आज 800 रुपये से 880 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम की कमजोरी दर्ज की गई है। कीमत में गिरावट आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,01,400 रुपये से लेकर 1,01,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 92,950 रुपये से लेकर 93,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी गिरावट आने के कारण कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। ,01,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 93,100 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,01,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,01,450 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,01,400 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 92,950 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,01,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,01,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 93,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 93,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,01,550 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना सस्ता हुआ है।

स्टॉक मार्केट में बीएलटी लॉजिस्टिक्स की जोरदार एंट्री, मजूबत लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। कंटेनर के जरिये ढुलाई करने और वेयर हाउस सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी बीएलटी लॉजिस्टिक्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 75 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 21.27 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 90.95 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर उछल कर 95.49 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 27.32 प्रतिशत का मुनाफा हो गया।बीएलटी लॉजिस्टिक्स का 9.72 करोड़ रुपये का आईपीओ 4 से 6 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 560.69 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 81.80 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 1,017.63 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 637.20 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 12.96 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नए ट्रक और एंसिलरी इक्विपमेंट की खरीदारी करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 22.68 प्रतिशत उछल कर 3.84 करोड़ रुपये और टोटल इनकम 21.36 प्रतिशत उछल कर 49.43 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि इस दौरान कंपनी पर कर्ज भी 13.56 प्रतिशत बढ़कर 13.65 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

अकासा एयर थाईलैंड के लिए शुरू करेगी दैनिक उड़ान

नई दिल्ली। विमान सेवा कंपनी अकासा एयर अगले महीने थाइलैंड के लिए दैनिक उड़ान शुरू करेगी। एयरलाइंस ने बताया कि वह 20 सितंबर से मुंबई से थाईलैंड के फुकेट के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उसके नेटवर्क में पहला और कुल मिलाकर छठा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य होगा। इसके लिए बुकिंग शुरू हो गयी है। फुकेट एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य है, खासकर अपने समुद्र तटों और जीवंत संस्कृति के लिए। मुंबई से फुकेट की उड़ान क्यूपी 0618 सुबह 7.45 बजे रवाना होगी और स्थानीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2.35 बजे वहाँ पहुँचेगी। वापसी की उड़ान क्यूपी 0619 स्थानीय समय के अनुसार 3.35 बजे फुकेट से रवाना होकर रात 7.15 बजे मुंबई में उतरेगी। अकासा एयर के सह-संस्थापक एवं मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी प्रवीण अय्यर ने कहा कि इस उड़ान के साथ एयरलाइंस न सिर्फ आज के समय के भारतीय पर्यटकों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है बल्कि थाईलैंड और भारत के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान कर रही है। अकासा एयर की सह-संस्थापक नीलू खत्री ने कहा कि थाईलैंड लंबे समय से भारतीय पर्यटकों की पसंद रहा है और वहाँ के लिए किफायती यात्रा की माँग लगातार बढ़ रही है।

शेयर बाजार के प्रति बढ़ा लोगों का रुझान, डीमैट अकाउंट्स की संख्या 20 करोड़ के पार पहुंची

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। निवेशकों की संख्या में तेजी आने के कारण जुलाई महीने में देश में डिमैट अकाउंट्स की संख्या 20 करोड़ के स्तर को भी पार कर गई है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में 29.80 लाख नए डिमैट अकाउंट खोले गए। इसके कारण डिमैट अकाउंट्स की कुल संख्या बढ़कर 20.21 करोड़ के स्तर पर आ गयी है। शेयर बाजार के निवेशकों की संख्या का अनुमान डिमैट अकाउंट्स की संख्या के आधार पर लगाया जाता है। डिमैट अकाउंट के जरिए ही कोई निवेशक शेयर बाजार में खरीद-बिक्री कर सकता है या अपने खरीदे हुए शेयरों को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या जितनी बढ़ेगी, उतना ही डिमैट अकाउंट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। जुलाई में 29.80 लाख नए डिमैट अकाउंट खुलने की बात

इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जुलाई महीने में शेयर बाजार में लगातार उठा पटक होता रहा। इसमें ज्यादातर समय बिकवाली का दबाव बना रहा। जुलाई के पहले जून महीने में सिर्फ 2.52 लाख नए डिमैट अकाउंट खोले गए थे। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइमरी मार्केट में बड़ी हलचल की वजह से डिमैट अकाउंट के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। शेयर बाजार में निवेश प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट के जरिए होता है। फिलहाल पहले से लिस्टेड शेयरों की खरीद-बिक्री करने वाले सेकेंडरी मार्केट को छोटे निवेशक ओवर वैल्यूड मान रहे हैं। ऐसे निवेशक आईपीओ में निवेश करके प्राइमरी मार्केट के जरिये शेयर बाजार में अपना पैसा लगा रहे हैं।

खुराना सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ रवि चंदर खुराना का कहना है कि प्राइमरी मार्केट में जुलाई महीने में हलचल काफी तेज हुई। इसकी वजह से बड़ी संख्या में नए ने लोगों ने डिमैट अकाउंट खुलवाकर शेयर बाजार में निवेश करने का रास्ता अपनाया शेयर बाजार में एक्टिव होने के लिए ऐसे निवेश को ने प्रायमरी मार्केट में आईपीओ के जरिए अपनी एंट्री की। खुराना का मानना है कि फिलहाल ज्यादातर आईपीओ अच्छे वैल्यूएशन के साथ लॉन्च किया जा रहे हैं। इससे नए निवेशकों को सेकेंडरी मार्केट की तुलना में प्राइमरी मार्केट ज्यादा पसंद आ रहा है। इसी वजह से जुलाई महीने में डिमैट अकाउंट्स की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है।

TV की इस 'नागिन' को जब डायरेक्टर ने कर दिया कमरे में बंद, बुरी तरह डर गई थी एक्ट्रेस

जैस्मिन भसीन

टीवी की दुनिया में जैस्मिन भसीन एक बड़ा नाम हैं. उन्होंने कई सारे सीरियल्स में काम किया है और वे सलमान खान के शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं. वे नागिन सीरियल के चौथे सीजन की लीड एक्ट्रेस रही हैं. अब जैस्मिन भसीन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने जीवन से जुड़े एक डरावने इंसिडेंट का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने इस दौरान अपने एक पुराने ऑडिशन को याद किया है जहां पर डायरेक्टर की हरकत ने एक्ट्रेस को बुरी तरह से डरा दिया था.

नागिन एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने कहा- मैं बॉम्बे ऑडिशन्स के लिए आई थी. जुहू के एक होटल में डायरेक्टर के साथ मेरी मीटिंग थी. कई सारी लड़कियां और एक्ट्रेस बाहर लॉबी में इंतजार कर रही थीं. कई सारे कॉर्डिनेटर्स भी वहां पर मौजूद थे. सभी मीटिंग के लिए अंदर जा रहे थे. जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा कि एक शख्स ड्रिंक कर रहा है और मुझसे ऑडिशन के लिए कह रहा है. मुझे जो कॉर्डिनेटर रूम तक लेकर गया था वो भी जा चुका था. मैं ये देख बहुत डर गई थी.

इसके बाद जैस्मिन ने आगे का इंसिडेंट शेयर करते हुए कहा- इसके बाद उस शख्स ने मुझे एक सीन करने के लिए दे दिया. मैंने उनसे कहा कि ठीक है सर मैं कल अपना सीन प्रिपेयर करते हुए आऊंगा. लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको तो ये सीन अभी ही करना होगा.

इसके बाद शख्स ने मुझे एक सीन दिया जिसके मुताबिक मेरा लवर जा रहा है और मुझे उसे रोकना है. मैंने उस सीन को किया लेकिन इसके बाद डायरेक्टर ने कहा- इस तरह नहीं अलग तरह से.

उसके बाद उस शख्स ने दरवाजा बंद कर दिया और वो कुछ और ही करना चाहता था. मैंने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और वहां से भाग निकली. उस दिन के बाद मैंने ये तय कर लिया था कि मैं कभी भी होटल रूम्स में ऐसी मीटिंग नहीं करूंगी.

जब सरेआम करीना कपूर ने कटरीना कैफ को कहा था 'भाभी', जाहिर की थी ये ख्वाहिश

बॉलीवुड के जो सबसे चर्चित अफेयर रहे हैं उनमें कटरीना कैफ और रणबीर कपूर का रिश्ता भी शामिल है. सलमान खान से ब्रेकअप के बाद कटरीना ने रणबीर कपूर से नजदीकियां बढ़ाई थीं. हालांकि इस रिश्ते को भी कोई मंजिल नहीं मिल पाई थी. दोनों अब शादी करके घर बसा चुके हैं और अपने पार्टनर के साथ हैप्पी लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं. हालांकि फैंस और सेलेब्स को उम्मीद थी कि दोनों आपस में ही शादी करेंगे.कटरीना कैफ और रणबीर कपूर ने लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट किया था. माना जा रहा था कि दोनों शादी करके अपने रिश्ते को नया नाम देंगे. उसी बीच करीना कपूर खान ने तो कटरीना कैफ को सरेआम भाभी तक कह दिया था. साथ ही उन्होंने कटरीना को लेकर एक ख्वाहिश भी जताई थी.

इस शो पर करीना ने कटरीना को कहा था 'भाभी'

कटरीना कैफ ने एक शो पर करीना कपूर को भाभी कहा था. जब रणबीर और कटरीना रिलेशन में थे तब करीना कपूर फिल्ममेकर करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण' में पहुंची थीं. उस वक्त रणबीर और कटरीना लिव-इन में रहने लगे थे और उनकी शादी की खबरें लगातार तूल पकड़ रही थीं.

करण जौहर अपने शो पर मेहमानों से रैपिड फायर राउंड में कई मजेदार सवाल भी करते हैं. वहीं करीना से उन्होंने रैपिड फायर राउंड में सवाल किया था कि वो किस एक्ट्रेस के साथ गे एनकाउंटर कर सकती हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा था को वो अपनी भाभी कटरीना कैफ के साथ गे एनकाउंटर करने में सहज महसूस करेंगी.

करीना ने विकी तो रणबीर ने आलिया से की शादी

साल 2016 में रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप हो गया था. उनका रिश्ता टूटने से उनके फैंस को भी बड़ा झटका लगा था. हालांकि जल्द ही दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे. रणबीर ने फिर आलिया भट्ट को डेट करना शुरू किया था. एक दूसरे के साथ अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद उन्होंने अप्रैल 2022 में शादी कर ली थी.

वहीं कटरीना ने साल 2019 में विकी कौशल को डेट करना शुरू किया था. विकी के साथ कटरीना ने साल 2021 में राजस्थान में धूमधाम से शादी की थी.

शिवभक्ति में डूबी दिखीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, तस्वीरें शेयर कर लिखा ये मंत्र, आप भी बोल पड़ेंगे 'हर-हर महादेव'

भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ना सिर्फ अच्छी एक्टिंग करती हैं, बल्कि वो एक जबरदस्त सिंगर भी हैं. भोजपुरी फिल्मों में मेल सिंगर्स तो बहुत हैं, लेकिन फीमेल सिंगर्स की गिनती कम है, लेकिन अक्षरा की गिनती एक्ट्रेस और सिंगर दोनों में होती है. इंस्टाग्राम पर अक्षरा को लाखों लोग फॉलो करते हैं और उनके पोस्ट को फैंस भर-भरकर प्यार भेजते हैं. इस बार अक्षरा सिंह ने दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो शिवभक्ति में लीन नजर आई.अगर आप अक्षरा सिंह को फॉलो करते हैं या उनके फैन हैं तो आपको ये भी पता होगा कि अक्षरा महादेव की बड़ी भक्त हैं. साल में कई-कई बार अक्षरा बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर जाती हैं और उसकी अपडेट्स भी इंस्टाग्राम पर देती हैं. अक्षरा जितनी मॉडल नजर आती हैं उतनी ही भक्तिभाव भी रखती हैं. इस बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों के जरिए फिर से बता दिया कि वो बड़ी शिवभक्त हैं. तस्वीरों के साथ अक्षरा ने एक मंत्र भी लिखा है जिसे सभी बोलते हैं.

अक्षरा सिंह ने तस्वीरों पर कौन सा मंत्र लिखा ?

11 अगस्त यानी आज अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वो शिवलिंग की पूजा करती और भक्तिभाव से शिवलिंग के पास आंखें बंद करके बैठी हैं. ये दो तस्वीरें देखकर ही आप समझ जाएंगे कि वो सच में शिवभक्त हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'नम: पार्वती पतये हर हर महादेव.' इस मंत्र का अर्थ है, 'मैं पार्वती के पति महादेव को प्रणाम करता हूं या करती हूं.'

ये तस्वीरें शिव मंदिर की हैं, जहां अक्षरा भक्ति में डूबी हैं. तस्वीरों में अक्षरा ने पिंक कलर का सूट पहना है, जबकि बालों में फीते लगाकर दो चोटी की है. ऐसा माना जा रहा है कि ये तस्वीरें उनके किसी अपकमिंग गाने या किसी फिल्म के शूट की हो सकती हैं. फिलहाल इन तस्वीरों के कमेंट बॉक्स में ज्यादातर लोगों ने हर हर महादेव लिखा है. ये मंत्र शिवभक्तों को अतिप्रिय है और इसके कई मायने भी हैं.

कैसा है अक्षरा सिंह का भोजपुरी फिल्मी करियर ?

2010 में रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते से अक्षरा सिंह ने भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके अपोजिट रवि किशन थे और इसके बाद अक्षरा ने खेसारी लाल, पवन सिंह, अरविंद अकेला जैसे बड़े भोजपुरी स्टार्स के साथ काम किया. फिल्मों के एक्टिंग के साथ-साथ अक्षरा सिंह गाने भी गाती हैं और अपने म्यूजिक वीडियो भी बनाती हैं. अक्षरा सिंह की पिछली रिलीज फिल्म रुद्र-शक्ति थी जो सफल रही.

जेल में बैठे-बैठे 25 करोड़ का दान

जैकलीन फर्नांडिस

के बर्थडे पर ठग सुकेश ने लिखा लव लेटर

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का आज 40वां जन्मदिन है, जिसे वो अपने करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं. उनके चाहने वाले देश-दुनिया के कोने से उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसी बीच 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद ठग सुकेश ने भी पत्र लिखा है. चाहे कोई त्योहार हो या फिर जन्मदिनज् जैकलीन के नाम सुकेश के पत्र सामने आते रहे हैं. दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश

चंद्रशेखर चिट्ठी लिखकर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को बर्थडे विश किया है.जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को चिट्ठी में लिखकर कहा कि- तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें. साथ ही जेल में बैठे-बैठे जैकलीन के बर्थडे पर 25 करोड़ रुपये दान किए हैं.

सुकेश ने जैकलीन को लिखी चिट्ठी

जेल में बंद ठग सुकेश पहले भी जैकलीन फर्नांडिस को चिट्ठी लिखते रहे हैं. अब बर्थडे पर जन्मदिन विश किया. साथ ही लिखा कि- उत्तराखंड में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हुई है. सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं और अपने घर और करीबियों को खो दिया है. मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए की मदद कर रहा हूं.योगदान कर रहा हूं. ताकी इसके इस्तेमाल से उन लोगों की देखभाल की जा सके

दरअसल एक्ट्रेस को लेकर सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने दावा किया कि वो और सुकेश एक दूसरे को डेट कर रहे थे. पर उन्होंने सभी बातों को गलत और झूठ बताया था. यूं तो जैकलीन और सुकेश की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं. दोनों की प्राइवेट तस्वीरों के बाद ही जैकलीन के लिए मुश्किलें शुरू हो गई थी. सुकेश की तरफ से जैकलीन को महंगे गिफ्ट देने की बातें भी कही गई हैं. इतना ही नहीं, इनमें कई महंगे गिफ्ट शामिल हैं- एक यॉट, एक घोड़ा, लग्जरी कारें और निजी जेट.

श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स बधानी कॉलेज, पठानकोट में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया तीज महोत्सव

दिव्य दिल्लीः पठानकोट (करूनीत रंधावा)

श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, बधानी कॉलेज में तीज का पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह और सांस्कृतिक उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती तरुणदीप कौर विशेष रूप से उपस्थित रहीं, जबकि संस्थान की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती तृप्ता पुंज ने इस मौके पर स्टाफ और छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्रीमती तृप्ता पुंज ने भारतीय संस्कृति और परंपरा में तीज महोत्सव के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह पर्व महिलाओं के समर्पण, आस्था और सौंदर्य का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा पति की दीघार्यु और कुंवारी कन्याओं द्वारा योग्य वर की प्राप्ति हेतु उपवास व पूजा-अर्चना के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में सजधज कर लोकगीतों पर नृत्य किया, झूले झूले और हाथों में मेहंदी रचाई। इस अवसर पर भांगड़ा, गीत-संगीत, सांझा संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। पारंपरिक व्यंजनों ने इस उत्सव की रंगत को और भी खास बना दिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रीमती प्रीत कौर, श्रीमती सुदेश शर्मा, श्रीमती वीना गुप्ता, श्रीमती सरता अभि, श्रीमती शल्लू, श्रीमती आशु और दरिंदर कौर समेत कई विशिष्ट महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में नीलाक्षी सैनी, डॉ नेहा तुली, डॉ सतिंदरजीत कौर, डॉ जसवंत कौर, डॉ अलका शर्मा, डॉ अलका डोगरा, डॉ विभूति शर्मा और अन्य फैकल्टी सदस्यों तथा छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। तीज उत्सव न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह सामाजिक जुड़ाव, आपसी भाईचारे और महिलाओं की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव का भी प्रतीक बन गया है.

हमीरपुर में भाजपा विधायक के चाचा के क्रशर पर पुलिस की छापेमारी, अवैध खनन का भंडाफोड़

दिव्य दिल्लीः हमीरपुर

सुजानपुर के पुंग खड्ड में भाजपा विधायक प्रवीण शर्मा के चाचा के स्वामित्व वाले एक क्रशर पर मंगलवार शाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश उपाध्याय के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध खनन गतिविधियाँ उजागर हुईं। यह क्रशर पिछले साल जुलाई से बंद घोषित था, बावजूद इसके वहां बड़े पैमाने पर पत्थरों का खनन किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 1 पोकलेन मशीन, 4 टिप्पर, 1 मिक्सर, 2 जेसीबी और लगभग 50 टिप्पर लोड ताजे निकाले गए बोल्डर जब्त किए हैं। खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को भी कार्रवाई में शामिल किया गया। मामला सुजानपुर थाना में क्ढउ की धारा 303(2) और खनिज अधिनियम 1957 की धाराओं 21 व 22 के तहत एफआईआर संख्या 0053/2025 में दर्ज किया गया है।

न्यूज फ्लैश

आइकिया ने दिल्ली में लॉन्च किया पहला स्टोर, पेश किया नया होम फर्निशिंग अनुभव

दिव्य दिल्लीः पश्चिम दिल्ली के सुभाष नगर मोड़ स्थित पैसिफिक मॉल में आइकिया इंडिया ने अपना पहला ऑफलाइन स्टोर खोला है। लगभग 15,000 वर्ग फुट में फैले इस स्टोर में वेस्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए आइकिया का क्यूरेटेड अनुभव उपलब्ध है, जिससे ग्राहक अपने घर की सजावट और फर्निशिंग जरूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं। यह स्टोर आइकिया की ओम्नीचैनल रणनीति का हिस्सा है, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग, बड़े स्टोर, सिटी स्टोर और ह्यप्लान एंड ऑर्डर पॉइंट्स शामिल हैं, ताकि ग्राहक कहीं से भी अपनी पसंद के अनुसार शॉपिंग कर सकें। स्टोर के उद्घाटन समारोह में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भारत में स्वीडन के दूतावास की डिप्टी हेड ऑफ मिशन एगनेस जूलिन, आइकिया इंडिया के सीएसओ पैट्रिक एंटोनी और कंट्री रीजनल मैनेजर सुजैन पल्वेरर मौजूद थे। स्टोर में 2,000 से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें से करीब 800 उत्पाद तुरंत खरीदकर ले जाने के लिए हैं। यहाँ डिजिटल टूल्स, इंटीरियर प्लानिंग सलाह, और इंस्पायरिंग रूम सेटिंग्स जैसी पर्सनलाइज्ड सेवाएं भी मिलती हैं। बड़े उत्पादों की ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। आइकिया इंडिया के सीईओ पैट्रिक एंटोनी ने कहा, "दिल्ली में अपना पहला स्टोर लॉन्च करना हमारे लिए गर्व की बात है। हमें उम्मीद है कि यह स्टोर दिल्लीवासियों को अपने घरों को नया रूप देने के लिए प्रेरित करेगा।" कंट्री एक्सपैंशन मैनेजर पूजा ग्रोवर ने बताया कि पैसिफिक मॉल जैसे जीवंत और समुदाय-केंद्रित स्थान पर स्टोर खोलना आइकिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आइकिया की दीर्घकालिक रणनीति के तहत, देश के अन्य प्रमुख शहरों में बड़े फॉर्मैट स्टोर्स, सिटी स्टोर्स और प्लान एंड ऑर्डर पॉइंट्स के जरिए ग्राहकों को किफायती और सुविधाजनक शॉपिंग अनुभव प्रदान किया जा रहा है। गुड़गांव और नोएडा में भी नए फुल-फॉर्मैट आइकिया स्टोर्स निमार्णाधीन हैं, जो कंपनी की भारत में विस्तार और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने की प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं।

फिल्मी स्टाइल में नाबालिगा की किडनैपिंग से सनसनी, पिस्तौल की नोंक पर जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर ले गए आरोपी

दिव्य दिल्लीःजवाली (ऊषा जरियाल)

जो घटनाएं अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सुनने को मिलती थीं, वैसी ही एक सनसनीखेज वारदात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के जवाली उपमंडल में सामने आई है। बड़ेला के हार गांव के नजदीक एक नाबालिगा को पिस्तौल की नोंक पर फिल्मी स्टाइल में किडनैप कर लिया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाबालिगा के भाई शेर अली ने जवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि वह अपनी बहन के साथ ट्रैक्टर से मिरथल स्थित घर लौट रहा था, तभी खङ नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो अचानक आई और कुछ लोगों ने उनकी बहन को जबरन ट्रैक्टर से नीचे उतारकर स्कॉर्पियो में बैठा लिया और मौके से फरार हो गए।इस दौरान किडनैपर्स ने दो अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। गनीमत रही कि उस समय कोई दोपहिया वाहन सामने नहीं आया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना के बाद से नाबालिगा के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया जाए और आरोपियों को सख्त सजा मिले।मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी जवाली वीरी सिंह ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और किडनैपर्स की धरपकड़ के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिगा को सुरक्षित बरामद किया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा ने फूंका ट्रंप-मोदी का पुतला, मुक्त व्यापार समझौते और लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ जताया रोष

पठानकोट (करुनीत रंधावा)

संयुक्त किसान मोर्चा के अवसर पर पठानकोट संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रंप और मोदी का पुतला फूंका। इस अवसर पर एक रैली निकाली गई जिसकी अध्यक्षता केवल सिंह कंग, बलदेव राज भौआ, पुरुषोत्तम कुमार बरोई, अमरीक सिंह, आईएस गुलाटी ने की। रैली में बलवंत सिंह, केवल कालिया, इकबाल सिंह, केवल सिंह कंग ने तोड़फोड़ की। ट्रेड यूनियन से सुरिंदर सहगल, सुभाष शर्मा ने मांग का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत सरकार पर कर मुक्त व्यापार के लिए दबाव बना रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि कृषि, अनाज, दूध उत्पादन और मछली व्यापार को कर मुक्त किया जाए। इससे भारत के किसान, दूध उत्पादक और मछुआरे बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने मांग की कि भारत सरकार अमेरिकी दबाव के आगे न झुके और मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकार करे।

डॉक्यूबे बना प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण कहानियों का अग्रणी मंच

ऑपरेशन माँ वृत्तचित्र जल्द होगा रिलीज

भारत में प्रीमियम और विचारोत्तेजक वृत्तचित्रों के क्षेत्र में अग्रणी डिजिटल मंच डॉक्यूबे अब अपनी मूल श्रृंखला का विस्तार कर रहा है और उद्देश्यपूर्ण, सामाजिक, राजनीतिक एवं मानवीय पहलुओं को उजागर करती कहानियाँ पेश कर रहा है। क्छ10 मीडिया नेटवर्क के अंतर्गत आने वाला यह मंच अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह ऐसी विषय-वस्तुओं पर केंद्रित है जो दर्शकों को गहराई से सोचने और सामाजिक संवाद स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। डॉक्यूबे ने अब तक कई प्रतिष्ठित और पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कारगिल 1999: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, 12 डिजिट मास्टरस्ट्रोकः द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आधार, द दुपट्टा किलर और फैनेटिक्स शामिल हैं। ये फिल्में भू-राजनीति, पहचान, अपराध और सामाजिक-राजनीतिक बदलाव जैसे ज्वलंत विषयों को व्यापक रूप से सामने लाती हैं। डॉक्यूबे ने अपनी सामग्री की विविधता बढ़ाते हुए विश्वसनीय और तथ्य-आधारित कहानियों की बढ़ती मांग को पूरा किया है।

इसी कड़ी में इसकी अगली बड़ी पेशकश ऑपरेशन माँ है, जिसका प्रीमियर 27 अगस्त को विशेष रूप से डॉक्यूबे पर होगा। यह वृत्तचित्र एक सच्ची और गहराई से भरी कहानी प्रस्तुत करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक माँ का प्रेम कश्मीर के कट्टरपंथ की चपेट में आए युवाओं को वापस मुख्यधारा में लाने की ताकत बनता है। यह फिल्म साहस, सामंजस्य और देशभक्ति की प्रेरणादायक यात्रा को दशार्ती है, जो भावनात्मक रूप से दर्शकों को छूती है और सामाजिक एकता का संदेश देती है। IN10 मीडिया नेटवर्क के प्रबंध निदेशक आदित्य पिट्टी ने इस दिशा में अपने विचार साझा करते हुए कहा, "हम हमेशा ऐसे उद्देश्यपूर्ण कंटेंट प्लेटफॉर्म बनाने में विश्वास करते हैं जो आज के दर्शकों की रुचि और जरूरतों को समझें।

राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर में नशीले पदार्थों के खिलाफ शपथ का आयोजन

दिव्य दिल्लीः नूरपुर (विनय महाजन)

राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर महाविद्यालय में नशीले पदार्थों के खिलाफ शपथ का आयोजन महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ दिलजीत सिंह के दिशा निर्देशन में नशा निवारण समिति के सदस्यों डॉ अनिल कुमार, प्रो मनजीत सिंह व प्रो मोनिका द्वारा किया गया । कार्यक्रम के शुरूआत में डॉ दिलजीत सिंह द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित कर उन्हें युवाओं में बढ़ रहे नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि ह्लनशा मुक्त भारत अभियानह्व जो कि भारत सरकार द्वारा पिछले चार-पांच वर्षों से नशीले पदार्थो से बचाव हेतु चलाया जा रहा है इसमें देश के युवाओं को इसके बारे में जागरूक करना आवश्यक है । नशीले पदार्थों का प्रचलन हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में पिछले कुछ वर्षों से बड़ा है व नशीले पदार्थों से जुड़े 5000 से भी ज्यादा मामले पुलिस विभाग द्वारा दर्ज किए गए हैं । विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे भांग, चरस, गांजा, हीरोइन अथवा चिट्टा आदि की अवैध व्यापार, ड्रग स्मगलिंग, ड्रग पैडलिंग व इससे जुड़े सरगनाओं को हिमाचल के कई जिलों में पकड़ा गया है। हिमाचल के कुछ जिलों जैसे कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला आदि में नशीले पदार्थ के सेवन व व्यापार के काफी केस दर्ज हुए हैं तथा बॉर्डर राज्यों जैसे पंजाब व जम्मू- कश्मीर आदि से नशीले पदार्थों की सप्लाई बरामद की गई है।

महाविद्यालय में मनाया गया संस्कृत दिवस

दिव्य दिल्लीः नगरोटा सूरियां (प्रेम स्वरूप शर्मा)

राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरियां में 12 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संस्कृत के महत्व से अवगत करवाना तथा इसमें निहित ज्ञान की भी जानकारी देना था। इसका आयोजन संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉ राजेश कुमार के द्वारा अन्य प्राध्यापकों के सहयोग से किया गया।

एबीवीपी ने नूरपुर में निकली तिरंगा यात्रा आज

दिव्य दिल्लीः नूरपुर (विनय महाजन)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला नूरपुर के जिला संयोजक प्रशांत रघुवंशी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए कार्य करती आई है। विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण और ध्येय राष्ट्र प्रथम है। विद्यार्थी परिषद अपने कार्यकताओं में राष्ट्रप्रथम की भावना को लाने का काम करती आई है। इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई नूरपुर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा नूरपुर महाविद्यालय से नूरपुर मेन बाजार तक गई। इस तिरंगा यात्रा में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारी संख्या में भागीदारी ली' इस अवसर पर प्रशांत ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा करवाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सब देशवासियों के मन में देश समर्पण का भाव आए। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना है।

तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है और लोगों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां के बारे में जागरूक करती है।

कामेंग किंग्स ने टीएनआर मोहित के साथ जर्सी और लोगो का किया अनावरण

दिव्य दिल्लीः
संस्कृति, जुनून और क्रिकेट के जोश का संगम कामेंग किंग्स टीम के जर्सी और लोगो अनावरण समारोह में देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश की तेची तगार टी20 चैंपियनशिप में अपनी शुरूआत से पहले कामेंग किंग्स ने युवा स्पिन गेंदबाज टीएनआर मोहित को भी पेश किया, जो राज्य के क्रिकेट भविष्य की उम्मीद हैं। यह टूनार्मेंट 1 से 16 सितंबर तक गुवाहाटी के मंगलदई क्रिकेट ग्राउंड में होगा, जिसमें कामेंग किंग्स आठ टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा करेगी। कार्यक्रम में अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य नाबाम विवेक और गेड़ा कबाक भी उपस्थित थे। मोहित ने कहा कि टीम की जर्सी पहनना पूरे क्षेत्र की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व है और वे इस सीजन में टीम के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित हैं। फ्रेंचाइजी प्रमुख प्रायोजक अरविंद टडकमल्ला ने कहा कि कामेंग किंग्स को समर्थन देना अरुणाचल की युवा शक्ति में निवेश है। टीम का लक्ष्य अरुणाचल क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और वह पूर्वोत्तर के क्रिकेट परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बनाने को तैयार है।

वर्ष दर वर्ष बढ़ती हरियाली की सौगातः निरंकारी मिशन का 'वननेस वन' अभियान

दिव्य दिल्लीः 13 अगस्त 2025: संत निरंकारी मिशन की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए 17 अगस्त 2025 को वननेस वन परियोजना के पांचवें चरण के तहत देशभर में हजारों सेवादार वृक्षारोपण करेंगे। यह अभियान केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और जैव विविधता के संरक्षण का संदेश देता है। 2021 में शुरू हुई इस पहल के तहत अब तक 600 से अधिक स्थलों पर लघु वनों का निर्माण हो चुका है, जहां दुर्लभ पक्षी भी लौट आए हैं। मिशन के सचिव श्री जोगिंदर सुखीजा ने बताया कि पौधों की देखभाल स्थानीय पर्यावरण के अनुसार जैविक खाद और आधुनिक तकनीकों से की जाती है, जिससे हरियाली दीर्घकालीन बनी रहे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्गदर्शन और पूज्य बाबा हरदेव सिंह जी के संदेश प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक हैं से प्रेरित यह अभियान मन की पवित्रता के साथ प्रकृति संरक्षण का समन्वय स्थापित करता है। निरंकारी मिशन की यह पहल समाज को पर्यावरण संरक्षण और सामंजस्य की दिशा में प्रेरित करती है।

महाविद्यालय में एंटी रैगिंग और नशा मुक्ति पर कार्यक्रम

दिव्य दिल्लीः नगरोटा सूरियां (प्रेम स्वरूप शर्मा)

राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरियां मे आज दिनाँक 12/08/2025 को राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग और नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष पर सर्वप्रथम सभी छात्रों को रैगिंग की समस्या और उसकी रोकथाम पर सहायक प्राध्यापक युवराज के द्वारा व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को जागरूक किया गया। इसके उपरांत महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. उपेन्द्र शर्मा के द्वारा सभी छात्रों को सम्बोधित किया गया। उन्होंने छात्रों को रैगिंग के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय मे आज से ही एंटी रैगिंग सप्ताह भी प्रारम्भ हुआ जो 18 अगस्त 2025 तक मनाया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे भाग में नशा मुक्ति पर सभी विद्यार्थियों ने शपथ ग्रहण की। महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ राजेश कुमार ने छात्रों को प्रतिज्ञा दिलवाई। विद्यार्थियों ने स्वयं नशा न करने और समाज में भी जागरूकता फैलाने की शपथ ली।

अवैध खनन सामग्री सहित 2 ट्रैक्टर ट्राली काबू

दिव्य दिल्लीः पठानकोट (करूनीत रंधावा)

पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध माइनिंग के खिलाफ चलाये गए अभियान के तहत आज दो ट्रैक्टर ट्रालियों को काबू किया गया जिनमें अवैध ढंग से किये खनन की सामग्री भरी हुई थी। इस सम्बंधित पुष्टि करते हुए डीएसपी संजीव यादव ने बताया कि पुलिस थाना डमटाल के एएसआई जैश लाल द्वारा अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों को जब भदरोआ के निकट रोका और खनन सामग्री व अन्य दस्तावेज दिखाने को कहा तो ट्रैक्टर चालकों द्वारा कोई भी दस्तावेज न दिखा पाने कारण उक्त दोनों भरी हुई ट्रैक्टर ट्रालियों को पुलिस थाने में लाया गया।

राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर के हिंदी विभाग ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एवं एंटी रैगिंग समिति ने एंटी रैगिंग शपथ दिलवाई

दिव्य दिल्लीः नूरपुर (विनय महाजन)

नूरपुर राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर में आज एंटी रैगिंग समिति ने प्रांगण में प्राचार्य डॉ॰ दिलजीत सिंह के कुशल मार्गदर्शन में एंटी रैगिंग शपथ ग्रहण एवं एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। छात्र व छात्रओ को इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉ॰ दलजीत सिंह ने कहां कि रैगिंग समाज के लिए एक कोढ़.की तरह है ,जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर देती है। रैगिंग के डर से बच्चे अपने भविष्य की तरफ आंख मूंद लेते हैं और अपने विकास एवं उन्नति को नजरअंदाज कर देते हैं।

बच्चों को एंटी रैगिंग की शपथ दिलाते समय उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह के दुर्व्यवहार और शोषण की घटनाएं लगातार होती रही है किंतु सरकार के प्रयासों से और माननीय न्यायालय के आदेशों से आज आज शिक्षण संस्थानों में एक सुहाग वातावरण बन पाया है। इसके चलते जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा से मुंह फेर लेते थे वह विद्यार्थी भी अब अपने भविष्य की ओर आशापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब हर विद्यार्थी अपने स्वर्णिम भविष्य के स्वप्न को पूरा करने का प्रयास करने की सोच रहा है।

वोट कटने और वोट बढ़ने की घटनाएंः लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल

दिव्य दिल्लीः नगरोटा सूरियां (प्रेम स्वरूप शर्मा)

नई दिल्ली। भारत के लोकतंत्र पर एक नया संकट मंडरा रहा है झ वह है वोटों का अनियमित तरीके से बढ़ना और कटना। यह सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा झ जनता के शासन झ पर सीधा आघात है। हाल ही में बेंगलुरु के महादेवपुरा क्षेत्र में फर्जी वोट पंजीकरण, डुप्लीकेट वोट और एक ही पते पर सैकड़ों वोट दर्ज होने की घटनाओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बिहार के कई क्षेत्रों में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के वोटों के कटने की खबरें सामने आ रही हैं। इन घटनाओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गहरा संदेह उत्पन्न कर दिया है। संविधान की मूल भावना यह रही है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और राजनीतिक दबाव से मुक्त संस्था हो।

लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में किया गया बदलाव झ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर कर, एक केंद्रीय मंत्री को जोड़ा गया झ इस निष्पक्षता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। अब जब चयन समिति में सत्तारूढ़ दल का बहुमत है, तो आयोग की स्वतंत्रता केवल कागजी रह गई है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397